RNI No.: MPBIL/2001/5256
DAVP Code : 128101
Postal Registration No. : भोपाल/म.प्र./581/2021-2023
Publish Date : Every Month Dt. 05
Posting Date : Every Month Dt. 15
Rs. 10/-

मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़

वर्ष 24 अंक 10 05 जून 2024

जगत विज़न

लोकसभा चुनाव 2024 में मिली मोदी को मात!

देश का मूड समझने में चूके मोदी

प्रेरणा स्त्रोत : स्व. श्री जगत पाठक

निर्भीक पत्रकारिता

संपादक	विजया पाठक
कार्यकारी संपादक	समता पाठक
दिल्ली संवाददाता	नीरज दिवाकर
पश्चिम बंगाल ब्यूरो चीफ	अमित राय
विशेष संवाददाता	अर्चना शर्मा

सम्पादकीय एवं विज्ञापन कार्यालय
भोपाल
एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल
मो. 98260-64596, मो. 9893014600
फोन : 0755-4299165 म.प्र. स्वत्वाधिकारी,

छत्तीसगढ़
4-विनायका विहार, रिंग रोड, रायपुर

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक,
विजया पाठक द्वारा समता ग्राफिक्स
एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र. द्वारा कम्पोज एवं जगत प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्लाट नं. 28 सुरभि विहार बीडीए रोड भेल भोपाल से मुद्रित एवं एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र. से प्रकाशित संपादक विजया पाठक। समस्त विवादों का कार्यक्षेत्र भोपाल सत्र-न्यायालय रहेगा। पत्रिका में प्रकाशित किये जाने वाले संपूर्ण आलेख एवं सामग्री की जिम्मेदारी लेखक एवं संपादक की होगी।

E-mail : jagat.vision@gmail.com
Website: www.jagatvision.co.in

मासिक द्विभाषी पत्रिका वर्ष 24 अंक 10 05 जून 2024

लोकसभा चुनाव 2024 में मिली मोदी को मात !

देश का मूड समझने में चूके मोदी

(पृष्ठ क्र.-6)

- विष्णुदेव साय सरकार के सुशासन के 06 माह 30
- छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के स्थान पर कौन ? 38
- अमीरों को छूट गरीबों की लूट 40
- गठबंधन बनाम क्षेत्रीय दलों की राजनीति में उभार 44
- कैसे खत्म होगी बाल मजदूरी 48
- बारूद के ढेर पर पाकिस्तान ! 51
- अमेरिका के इतिहास में पहली बार पूर्व राष्ट्रपति अपराधिक मामलों में दोषी... 56
- ठेके की नौकरियों में गुम होता भविष्य 60
- Water Pollution an Invitation to health diseases 62

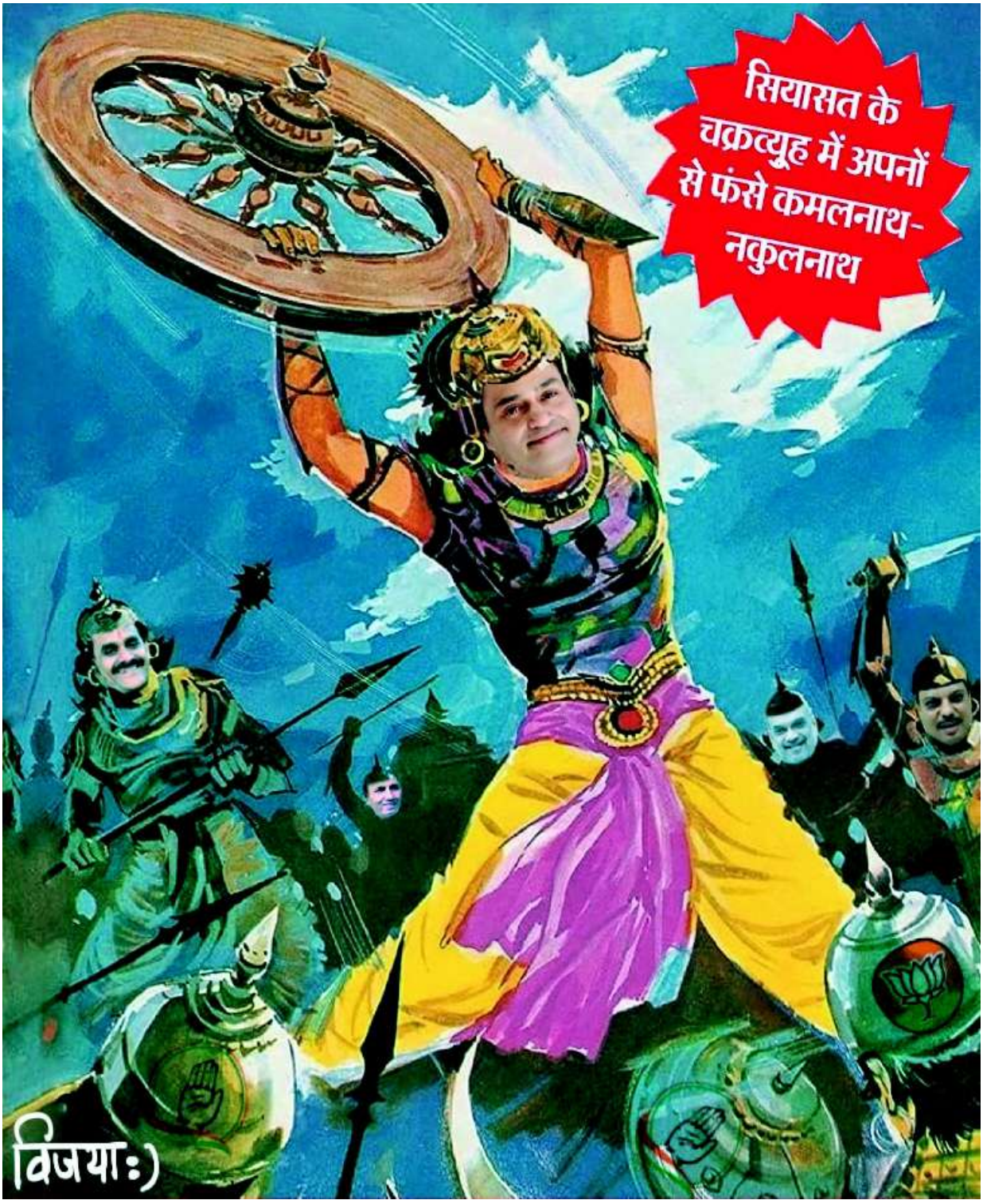
सियासत के चक्रव्यूह में अपनों से फंसे कमलनाथ-नकुलनाथ
विजया:)

पहली बार गठबंधन में फंसे मोदी

लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के साथ ही मोदी सरकार गठबंधन के फेर में फंस गई है। 543 सदस्यीय लोकसभा में किसी भी पार्टी के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है। बहुमत के लिए 272 सीटें चाहिए, मगर भाजपा के पास महज 240 सीटें हैं, मगर उसके एनडीए गठबंधन के पास पर्याप्त 292 का आंकड़ा है। वहीं, इंडिया गठबंधन के पास 234 का आंकड़ा है। सरकार बनाने में सारा दारोमदार दो क्षेत्रीय पार्टियों टीडीपी और जदयू पर टिका। इनका साथ भाजपा को मिला और मोदी एक बार फिर तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए। यह भी पहला अवसर है जब मोदी गठबंधन की सरकार के मुख्या के तौर पर काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहली बार वास्तविक रूप से गठबंधन सरकार चलाने की चुनौती मिल रही है। वह 22 साल तक पूर्ण बहुमत वाली बीजेपी सरकार चलाने के अभ्यस्त रहे हैं। लेकिन, यह भी तय है कि उन्हें सरकार चलाने का जो जनादेश मिला है, उसमें गठबंधन करना जरूरी है। नरेंद्र मोदी को अभी तक भाजपा की प्रचंड बहुमत सरकार चलाने का अनुभव रहा है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद मोदी सरकार भी गठबंधन की सरकार थी। 2014 में भाजपा को 282, जबकि 2019 में 303 सीटें मिली थीं। ऐसे में गठबंधन हो या न हो, भाजपा की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मोदी जब 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब भी वह भाजपा के पूर्ण बहुमत वाली सरकार के मुखिया थे। उनके पास अभी तक ऐसे गठबंधन की सरकार चलाने का अनुभव नहीं है, जिसमें भाजपा ने किसी अन्य दलों के समर्थन से सरकार चलाई हो। ऐसे में नायडू और नीतीश को संभालने में उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है। टीडीपी और जदयू ने मिलकर 28 सीटें जीती हैं और एनडीए को बहुमत के 272 के आंकड़े के पार तक पहुंचाया। अभी एनडीए को 292 सीटें मिली हैं। यानी अगर इन दोनों पार्टियों की सीटें निकाल दी जाएं तो एनडीए के पास केवल 264 सीटें ही रह जाएंगी। ऐसे में दोनों की एनडीए में अहमियत काफी बढ़ गई है। पीएम मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को अपने साथ लेकर चलने की होगी। नायडू और नीतीश 2014 में नरेंद्र मोदी के पहली बार प्रधानमंत्री बनने पर बीजेपी के विरोधी खेमे में रह चुके हैं और इस लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एनडीए में वापसी की है। कहा जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक समय खुद को पीएम पद का दावेदार भी बताते थे। उनका यह सपना अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। मौजूदा परिस्थितियों बीजेपी को सिर्फ टीडीपी और जेडीयू के सहयोग की ज्यादा आवश्यकता है, बाकी तरफसे ज्यादा अड़चनें पैदा होने के हालात नहीं है। लेकिन आने वाले समय में इतना तो तय है कि ये दोनों सहयोगी कभी न कभी मोदी सरकार को मझधार में छोड़ने पर विचार भी कर सकते हैं। तब देखने वाली बात होगी कि उस परिस्थिति में मोदी क्या स्टंट अपनाते हैं।

विजया पाठक

लोकसभा चुनाव 2024 में मिली मोदी को मात !

देश का मूड समझने में चूके मोदी

बीजेपी का 370 और एनडीए के लिए 400 पार का नारा सच साबित नहीं हुआ। भाजपा और एनडीए को भारी नुकसान हुआ है। एनडीए 292 सीटों पर और इंडिया गठबंधन ने 234 सीटों पर जीत का परचम लहराया है। माना जा रहा है कि बीजेपी और एनडीए के मौजूदा सांसदों से नाराजगी पार्टी को भारी पड़ी है। जाहिर है, नरेंद्र मोदी का जादू 2014 ओर 2019 की तरह नहीं चला है। यह नतीजे एग्जिट पोल्स में दिखाए गए नतीजों और भाजपा के वादों से एकदम उलट हैं। बता दें कि उत्तरप्रदेश में चुनाव से कुछ महीने पहले ही अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। इसे काफी प्रचारित भी किया गया था और चुनाव प्रचार में भी इसे मुद्दा बनाया गया था। खैर, अब देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन गई है। जानकारों की मानें तो भले ही अभी मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है लेकिन वे शायद इस बात को भूल गये हैं कि आगामी कुछ ही दिनों में उनकी पार्टी से समर्थन वापस लेकर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इंडिया अलायंस के साथ मिलकर सरकार बनाने की जुगत में जुट जायेंगे। 240 सीटें हासिल कर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, लेकिन बहुमत के आंकड़े से दूर है। सरकार बनाने के लिए बीजेपी को अब टीडीपी और जेडीयू सहित सहयोगी दलों का सहारा लिया। विपक्षी गठबंधन इंडिया को 234 सीटें मिली हैं। 2024 में देश की जनता ने एक बार फिर खंडित जनादेश दिया है। हालांकि बीजेपी इस चुनाव में अपनी जीत मानकर चल रही है लेकिन सही मायने में कहा जाये तो यह मोदी की हार है। जो 400 पार के सपने देख रहे थे वह लगभग आधे में ही सिमट गये हैं। यह भी सच है कि देश के अंदर जैसा माहौल बनाया गया था उससे तो यही लगता था कि बीजेपी आसानी से पूर्ण बहुमत को हासिल कर लेगी लेकिन नहीं हुआ। क्योंकि नरेन्द्र मोदी देश की जनता का मूड ही नहीं समझ पाये। अब बड़ा सवाल यह उभर रहा है कि आखिर मोदी गठबंधन की इस सरकार को आगे कहां तक संभाल सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि मोदी सरकार में जो दल शामिल हैं उन पर मौकापरस्ती का थप्पा लगा हुआ है। वह दल कब तक बीजेपी के साथ है और कब साथ छोड़ सकते हैं यह कहां नहीं जा सकता है। यह बात भी समझनी होगी कि इस बार विपक्ष काफी मजबूत है। 2024 और 2019 के जैसा नहीं है। सरकार को सदन चलाने में परेशानी होगी। साथ ही जो बड़े-बड़े फैसले लेंगे होंगे उनमें अब काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। कहा जा सकता है कि मोदी सरकार अब बैशाखी पर आ गई है। बगैर सहारे के वह चल नहीं सकती है।

विजया पाठक

लोकसभा चुनाव के नतीजों को बाद नई सरकार का गठन हो चुका है। पीएम मोदी लगातार तीसरी बार पीएम पद की शपथ ले चुके हैं। मंत्रिमंडल का बंटवारा भी हो चुका है। इसके बाद भी एक चीज पर चर्चा अभी तक थमने का नाम नहीं ले रही है। वो है इस चुनाव में बीजेपी का पिछली बार की तुलना में खराब प्रदर्शन। भाजपा ने थोड़े अति आत्मविश्वास के कारण अपने पैर पर कुल्हाडी मार ली। पार्टी के लिए विशेष रूप से हानिकारक भाजपा सांसदों का यह कहना था कि मोदीजी को 400 सीटों की आवश्यकता है ताकि संविधान में संशोधन किया जा सके। सोशल मीडिया और चुनावी प्रचार के माध्यम से कांग्रेस ने यह प्रचार किया कि संविधान बदलने से एससी और ओबीसी के लिए आरक्षण समाप्त हो सकता है। अफवाह ने इतना तूल पकड़ लिया कि भाजपा को डैमेज कंट्रोल करना पड़ा। यही कारण है कि आखिरी मिनट में पीएम मोदी का चुनाव अभियान घबराहट भरा लग रहा था। उन्होंने अपने अभियान को मुस्लिम जन्म दर के बारे में डर फैलाना, मंगलसूत्र छीनना, मुजरा और चोरी के नल की बातें की ओर मोड़ दी। बीजेपी के आक्रामक ध्रुवीकरण वाले चुनाव प्रचार ने विपक्ष को एकजुट कर दिया। सत्तारूढ़ गठबंधन पूरी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसे था। सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन के चुनाव अभियान में इस बार बड़ा स्विंग देखने को मिला। एनडीए ने शुरूआती चरण में अपनी सरकार की आर्थिक उपलब्धियों और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को सामने रखा और बाद में यह संकीर्ण सामाजिक एजेंडे की ओर शिफ्ट हो गया। शुरूआत में इंडिया गठबंधन दिशाहीन दिख रहा था लेकिन जल्द ही वह लड़ाई लड़ने के लिए एकजुट हुआ। बीजेपी के आक्रमक

भाजपा ने थोड़े अति आत्मविश्वास के कारण अपने पैर पर कुल्हाडी मार ली। पार्टी के लिए विशेष रूप से हानिकारक भाजपा सांसदों का यह कहना था कि मोदीजी को 400 सीटों की आवश्यकता है ताकि संविधान में संशोधन किया जा सके। सोशल मीडिया और चुनावी प्रचार के माध्यम से कांग्रेस ने यह प्रचार किया कि संविधान बदलने से एससी और ओबीसी के लिए आरक्षण समाप्त हो सकता है। अफवाह ने इतना तूल पकड़ लिया कि भाजपा को डैमेज कंट्रोल करना पड़ा। यही कारण है कि आखिरी मिनट में पीएम मोदी का चुनाव अभियान घबराहट भरा लग रहा था।

नीतीश कुमार और चन्द्रबाबू नायडू
साथी या बैसाखी!

बीजेपी के लिए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार बहुत अहम हैं। मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में इनका योगदान है। टीडीपी को 16 और जदयू को 12 सीटें मिली हैं और दोनों मिलकर नई सरकार में 28 सीटों का योगदान दिया है। जनता दल यूनाइटेड प्रमुख और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा तेलगू देशम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के बिना मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे। लेकिन अतीत में ये भी कई बार एनडीए छोड़ चुके हैं। नीतीश कुमार और नायडू की पार्टी ने खुलकर कहा है कि वो एनडीए के साथ हैं लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि दोनों एनडीए में बेहतर डील और अपनी शर्तों पर रहेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो नीतीश और नायडू के लिए इंडिया गठबंधन भी कोई अछूत नहीं है। कहा भी जा रहा है कि इनका साथ है या बैशाखी है। एनडीए गठबंधन में इन दोनों दलों की सदस्य संख्या सबसे अधिक है। मोदी के मंत्रीमंडल में भी इन दोनों पार्टियों को कोई बड़ा पद नहीं दिया गया है। जबकि इन्होंने अपने लिए महत्वहपूर्ण विभाग की बात कही थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि यह गठबंधन कितने दिनों तक टिक पाता है।

ध्रुवीकरण वाले चुनाव प्रचार ने विपक्ष को एकजुट कर दिया। सत्तारूढ़ गठबंधन पूरी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसे था। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भी जहां पर बीजेपी के पास बेहद लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, वहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र

लोकसभा-2024 में बढ़ी
विपक्ष की ताकत

लोकसभा चुनाव 2024 में विपक्ष काफी मजबूत स्थिति में उभरा है। जो विपक्ष 2014 और 2019 में हाशिए पर था और उसकी सीटें काफी कम थी, लेकिन 2024 में वह 234 की संख्या के साथ मोदी को चुनौती देने के लिए खड़ा हो गया है। विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है जिसकी, संख्या 99 है जबकि दूसरी बड़ी पार्टी सपा है जिसकी सीटे 37 हैं, उसके बाद टीएमसी 31, सीटों के साथ तीसरे स्थान पर है। विपक्ष के इस आंकड़े के साथ निश्चित ही आने वाले समय में मोदी सरकार को अपने एकतरफा फैसले लेने में काफी परेशानी होगी। पिछले दो कार्यकाल में मोदी ने जो फैसले लिए हैं वैसा अब नहीं होने वाला है। इसके साथ ही विपक्ष का मजबूत होना देश के हित में भी होगा। कहा भी जाता है कि लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना लोगों के हित में होता है।

मोदी ही चुनाव प्रचार में छाए रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान रिकॉर्ड तोड़ 206 जनसभाएं की। चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री ने 80 साक्षात्कार भी दिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 107 चुनावी कार्यक्रम किए। इस आम चुनाव में

लोकसभा-2024 में
हारे दिग्गज

लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी, काँग्रेस सहित कई पार्टियों के कई दिग्गज चुनाव हार चुके हैं। मोदी लहर के बावजूद भी बीजेपी से स्मृति ईरानी, मेनका गांधी चुनाव हार गई है।

उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट से 2019 में राहुल गांधी को हराने वाली स्मृति ईरानी इस बार चुनाव हार गई है। कांग्रेस प्रत्याशी किशोरी लाल ने स्मृति ईरानी को 1.5 लाख से अधिक वोटों से पराजित किया है।

पूर्व केन्द्रीय मंत्री और बीजेपी की कद्दावर नेता मेनका गांधी भी इस बार उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर सीट से चुनाव हार गई। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने राम भुवन निषाद ने मेनका गांधी को हराया।

मध्यप्रदेश के राघोगढ़ सीट से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को भी हार का सामना करना पड़ा है। बीजेपी के रोडमल नागर ने सिंह को लगभग 1.5 लाख वोटों से हराया है।

मध्यप्रदेश के सबसे हॉट सीट छिन्दवाड़ा से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को इस बार हार सामना करना पड़ा है। छिन्दवाड़ा सीट पिछले कई वर्षो से कमलनाथ के हाथों में थी।

पीडीपी की अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती भी चुनाव हार गई। नेशनल कांन्फ्रेंस की प्रत्याशी अल्ताफ अहमद ने मेहबूबा को 2.81 लाख वोटों से शिकस्त दी है।

बारामूला से निर्दलीय प्रत्याशी अब्दुल राशिद शेख ने नेशनल कांन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला को 2 लाख से अधिक वोटो से हराया है। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के कद्दावर नेता माने जाते है।

एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन में मुद्दों पर पूरी तरह साफ तस्वीर थी। नरेन्द्र मोदी और राहुल गांधी दोनों ही पूरे चुनाव में अपने पिच पर टिके रहे। इसमें कहीं-कहीं नरेन्द्र मोदी को सफलता मिली तो कहीं राहुल गांधी को बीजेपी के अजेय रथ रोकने में मदद मिली।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने लगातार एनडीए के लिए 400 पार' का नारा दिया है। कुछ एग्जिट पोल्स ने भी एनडीए को 400 पार जाते हुए दिखाया है। लेकिन, असल में देश के चुनावी इतिहास में केवल एक बार ही किसी पार्टी (कांग्रेस) को 400 से ज्यादा सीटें मिली हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने एनडीए गठबंधन के साथ 353 सीटों पर जीत दर्ज कर सत्ता का ताज अपने सिर सजाया था। वहीं, कांग्रेस को यूपीए गठबंधन में केवल 91 सीटों से संतोष करना पड़ा था। इसके

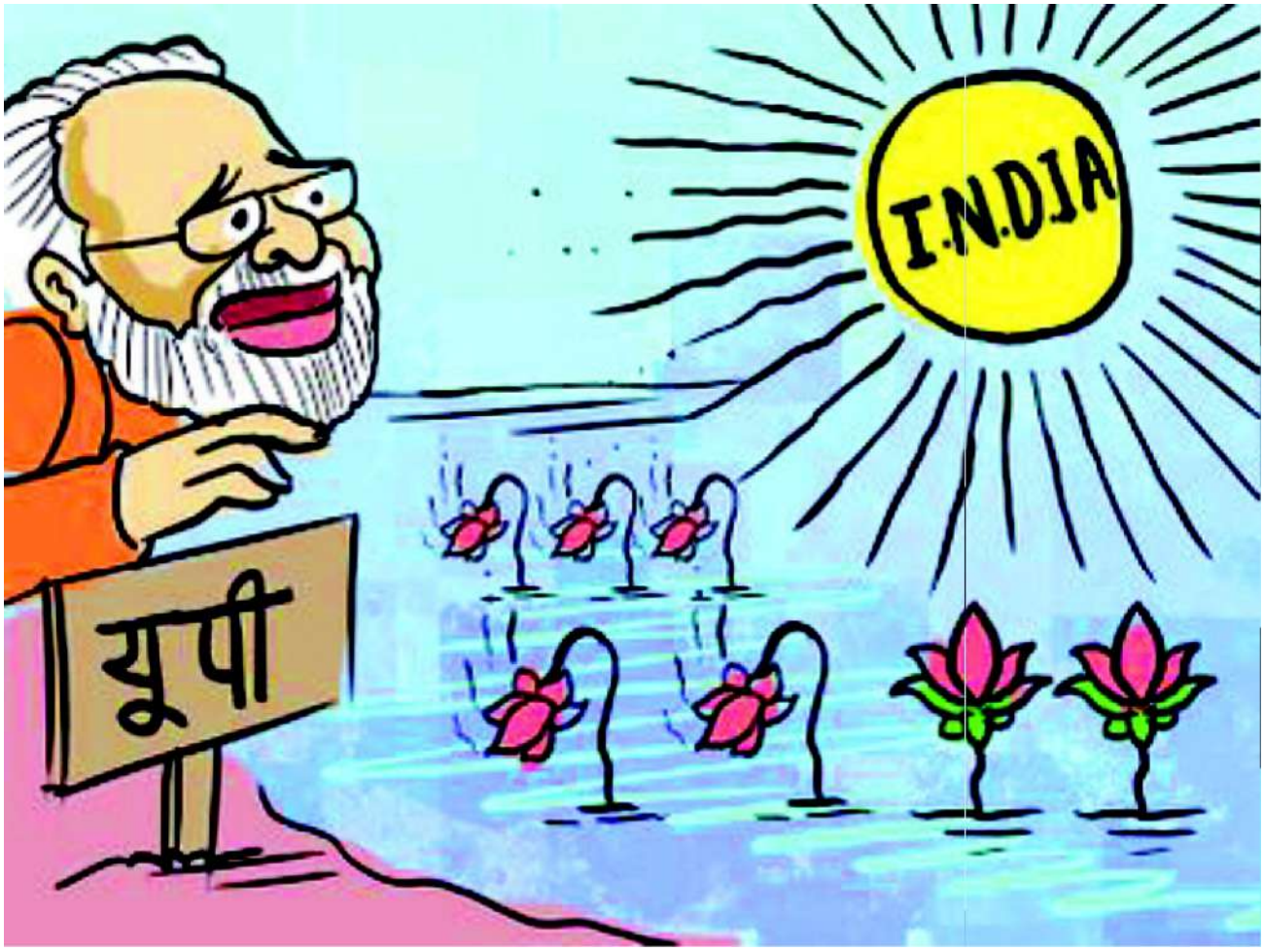

अतिरिक्त 98 सीटें पर अन्य पार्टियां रही थीं।

लगभग 06 हफ्तों तक चला 18वीं लोकसभा का चुनाव चला। एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा तो पार कर लिया, लेकिन बीजेपी 240 सीटें ही जीत सकी। सत्तारूढ़ एनडीए ने 292 तो विपक्षी इंडिया गठबंधन ने 234 सीटें जीत हासिल की। इस बार सबसे बड़ा नुकसान एनडीए को हुआ। 2019 के चुनाव में एनडीए 350 के पार चला गया था, लेकिन इस बार 300 सीट भी नहीं जीत सका। वहीं, विपक्ष का एकजुट होना उसके लिए फायदेमंद साबित हुआ। सबसे बड़ा झटका बीजेपी को लगा है। क्योंकि 2014 और 2019, दोनों ही बार बीजेपी ने अपने बूते बहुमत हासिल कर लिया था। लेकिन इस बार बीजेपी बहुमत के जादुई आंकड़े 272 से दूर रह गई। इस चुनाव में कई बड़े दिग्गज हार गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार वाराणसी से चुनाव जीते। हालांकि, 2014 और 2019 की तुलना में 2024 में उनकी जीत सबसे छोटी रही। बीते दो चुनावों में तीसरे नंबर पर रहे कांग्रेस के अजय राय ने इस बार अच्छा प्रदर्शन किया। पीएम मोदी ने ये चुनाव 1.52 लाख वोटों के अंतर से जीता जबकि, पिछली बार उनकी जीत का अंतर 4.79 लाख वोटों का रहा था। देश के

2019 के चुनाव में एनडीए 350 के पार चला गया था, लेकिन इस बार 300 सीट भी नहीं जीत सका। वहीं, विपक्ष का एकजुट होना उसके लिए फायदेमंद साबित हुआ। सबसे बड़ा झटका बीजेपी को लगा है। क्योंकि 2014 और 2019, दोनों ही बार बीजेपी ने अपने बूते बहुमत हासिल कर लिया था। लेकिन इस बार बीजेपी बहुमत के जादुई आंकड़े 272 से दूर रह गई।

उत्तरप्रदेश में सपा और काँग्रेस ने बिगाड़ा भाजपा का सियासी गणित

लोकसभा चुनाव में राममंदिर मुख्य मुद्दा होने के बावजूद बीजेपी उत्तर प्रदेश की फैजाबाद लोकसभा सीट से भी हार गई। इस सीट से हारने से पूरे देश में बीजेपी काफी आलोचना भी हो रही है और अचंभा भी हो रहा है। अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को मजबूती दी है, जिससे सत्तारूढ़ भाजपा को झटका लगा तय है। विभिन्न अनुमानों को झुठलाते हुए सपा भाजपा के लिए एक मजबूत चुनौती बनकर उभरी है। सपा उत्तर प्रदेश में 37 सीटों पर आयी है जबकि बीजेपी इससे भी कम पर। वहीं कांग्रेस ने भी इस बार उप्र में 2014 और 2019 के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया है। कांग्रेस अमेठी सीट भी बीजेपी से छीन ली है। 2019 के लोकसभा चुनावों में, सपा यूपी में सिर्फ 5 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, क्योंकि तब उसने बसपा के साथ गठबंधन के तहत राज्य की 80 सीटों में से 37 सीटों पर चुनाव लड़ा था। तब बीजेपी ने 62 सीटों पर जीत हासिल की थी जबकि बसपा को 10 सीटें मिली थीं। इस बार सपा ने 62 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि उसकी सहयोगी कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी।

पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के बाद मोदी दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं, जो लगातार तीसरी बार सत्ता में आए हैं। इस चुनाव में मोदी सरकार के 19 मंत्रियों में से 18 जीत गए। जबकि, अमेठी से स्मृति ईरानी हार गईं। उन्हें कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा ने 1.67 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया। गुजरात की गांधीनगर सीट से गृहमंत्री अमित शाह ने सबसे बड़ी जीत हासिल की। उन्होंने 7.44 लाख वोटों से कांग्रेस की सोनल पटेल को चुनाव हराया। इस चुनाव में मोदी सरकार में मंत्री रहे दर्जनों नेता हार गए। हारने वाले मंत्रियों में राजीव चंद्रशेखर (तिरूवनंतपुरम), अर्जुन मुंडा (खूंटी), महेंद्र नाथ पांडे (चंदौली) और अजय मिश्रा टेनी (लखीमपुर खीरी) शामिल हैं। NDA की तुलना में INDIA गठबंधन ज्यादा फायदे में रहा। INDIA गठबंधन की

चौकानें वाले रहा लोकसभा का चुनाव

प्रमोद भार्गव

18वीं लोकसभा चुनाव के आए परिणामों के बाद स्थिति साफ हो गई। 64 करोड़ 02 लाख मतदाताओं ने अपने आमूल्य मत से अपना प्रतिनिधि चुन लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाति और मजहब को हवा देकर 400 पार जाने का दंभ भरा था, लेकिन मतदाता ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को 292 सीटों पर सिमटाकर जता दिया कि अंततः लोकतंत्र में जीत या हार का आधार जागरूक मतदाता ही है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ और निष्पक्षता का दंभ भरने वाले समाचार चैनलों ने एग्जिट पोल में भाजपा को 300 और राजग को 400 पार करा दिया था। लेकिन चुनाव नतीजों ने साफकर दिया कि वास्तविक परिणामों को कुछ हजार मतदाताओं से बात करके कदापि निर्णय को नहीं जाना जा सकता है। परिणाम पूर्व समाचार चैनलों द्वारा कराए गए अनुमानित सर्वेक्षण धराशायी दिखाई दिए है। जिस इंडिया गठबंधन को बहुत पीछे बताया जा रहा था। उसने 234 सीटें लाकर जता दिया है कि मतदाता डूबते जहाज को भी किनारे लगा सकता है। खासतौर से उत्तरप्रदेश में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। यहां हिंदु मतों को नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जिस तरह से ध्रुवीकृत किया वह उत्तरप्रदेश में भाजपा को उल्टा पड़ता दिखाई दिया है। मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा ने दिसंबर 2023 में नए मुख्यमंत्रियों का चयन जातिगत आधार पर बहुत सोच-समझकर किया था, इसका उसे लाभ नहीं मिला।

मध्यप्रदेश में मोहन यादव को इसलिए मुख्यमंत्री बनाया गया था जिससे उत्तरप्रदेश और बिहार के यादव मतदाताओं को साधा जा सके। लेकिन, उत्तरप्रदेश में अखिलेश यादव ने यादव, मुसलमान और बहुजन समाज पार्टी के वोट लेकर अपनी स्थिति मजबूत कर ली। इंडिया गठबंधन का सहयोगी दल होने का लाभ अखिलेश को पांच राज्यों- उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक और बिहार में जबरदस्त सीटें बढ़ी हैं। इन पांचों राज्यों में INDIA गठबंधन ने 100 सीटों पर जीत हासिल की। जबकि, पिछले चुनाव में INDIA गठबंधन की पार्टियों ने यहां की 18 सीटें ही जीत

मिला। नतीजतन उत्तरप्रदेश में जाति और धर्म की राजनीति भाजपा के काम नहीं आई। 80 में से करीब 37 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में, 36 भाजपा के, 07 कांग्रेस के और दो राष्ट्रीय लोकदल के खाते में चली गई। ये भाजपा के लिए बड़ा झटका है। क्योंकि राम मंदिर निर्माण के चलते माना जा रहा था कि सभी जातियों का वोट भाजपा को मिलेगा और वह अधिकतम सीटें जीत जाएगी। लेकिन जातीय और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण ने सपा के पक्ष में चला गया। भाजपा के पास मौजूदा वक्त में राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश और बिहार में कोई प्रमुख यादव नेता नहीं है। इस नाम के सहारे इन राज्यों में जो बंसी बजाने का उपाय किया था, वह बन ही नहीं पाई। चूंकि छत्तीसगढ़ में आदिवासी विष्णुदेव को मुख्यमंत्री बना दिया गया था, इसलिए मध्यप्रदेश में फिर से ओबीसी कार्ड खेलना शिखर नेतृत्व को ऐसा लग रहा था कि यह कार्ड उत्तरप्रदेश और बिहार में भी चल जाएगा। मध्यप्रदेश में केंद्रीय नेतृत्व ने मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर यह संदेश देने की कोशिश की थी कि उत्तरप्रदेश और बिहार के यादवों को यह संदेश पहुंच जाएगा कि भाजपा का साथ दिया तो मोहन यादव जैसे साधारण कार्यकर्ता की तरह इन राज्यों में भी भाजपा बहुमत में आती है तो यादवी मुख्यमंत्री का कार्ड खेल सकती है। लेकिन, उत्तरप्रदेश के यादवों में भाजपा मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा जगा नहीं पाई। दरअसल मोहन यादव के चेहरे को महत्व देकर भाजपा ने उत्तर प्रदेश की पिछड़े वर्ग की 54 प्रतिशत आबादी को साधने की कोशिश की थी। इसमें 20 प्रतिशत यादव समाज के मतदाता हैं। उत्तरप्रदेश में लोकसभा की 80 सीटे हैं और प्रधानमंत्री बनने का मार्ग यहीं से खुलता है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटे हैं। यहां पिछड़े वर्ग की कुल आबादी 63 प्रतिशत है, जिसमें 14 प्रतिशत यादव बताए जाते हैं। अतएव मोहन यादव के माध्यम से यादव मतदाताओं को साधने की यह कवायद आम चुनाव में भाजपा को लाभदायी साबित होने की उम्मीद थी, जिसपर परिणाम आने के बाद पानी फिर गया। राजस्थान में ब्राह्मण चेहरे के रूप में भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया था। जिससे राजस्थान में ब्राह्मणों समेत अन्य सवर्ण समाज के मतदाताओं का मत भाजपा की झोली में चला जाए, लेकिन ऐसा पूरी तरह हो नहीं पाया। कांग्रेस के लिए यह बड़ी सफलता है। क्योंकि सात माह पहले भी कांग्रेस को राजस्थान अशोक गहलोत की सरकार गंवानी पड़ी थी। हालांकि राजस्थान में मुख्यमंत्री बनने की असली हकदार वसुंधरा राजे सिंधिया थीं, उन्हें किनारा करके भजनलाल के माथे पर मुख्यमंत्री पद का आदेश चास्पा कर दिया था। संभव है, वसुंधरा ने अपनी ताकत दिखाने के नजरिए से भाजपा को नुकसान पहुंचाने का काम किया हो? अन्यथा राजस्थान में भाजपा लोकसभा की सभी सीटें जीतती रही है। मध्यप्रदेश में सभी 29 सीटों पर भाजपा बढ़त बनाए हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ चुनाव हार रहे हैं। इंदौर में कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने नाटकीय ढंग से अंतिम दिन अपना पर्चा वापस लेकर भाजपा का दामन थाम लिया था। कांग्रेस का प्रत्याशी ही इंदौर लोकसभा सीट पर नहीं रह गया था। जाति और धर्म की राजनीति की तरह यह नाटकीय घटनाक्रम भी इंदौर के मतदाताओं को भाया नहीं और इंदौर के जागरूक मतदाताओं ने अपनी नाराजी जताते हुए 2 लाख से भी ज्यादा वोट नोटा को दिए। मध्यप्रदेश में भाजपा ने जो सभी सीटें जीती हैं, उसमें न तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह का कोई करिश्मा काम आया है और न ही मोहन यादव ने कोई चमत्कार दिखाया है। यहां की विजय का श्रेय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान और उनकी लाडली बहनों को जाता है। बहरहाल मतदाता ने इस चुनाव में हर प्रकार के अतिवाद को नकारा है। धर्म और जाति की आक्रामकता ने उत्तरप्रदेश में नुकसान पहुंचाया वैसा ही राजस्थान, हरियाणा ने किया। अतएव देश के नेताओं को यह चुनाव एक सबक है, कि वे संतुलन और समन्वय की राजनीति से पेश आएं।

उत्तरप्रदेश में जाति और धर्म की राजनीति भाजपा के काम नहीं आई। 80 में से करीब 37 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में, 36 भाजपा के, 07 कांग्रेस के और दो राष्ट्रीय लोकदल के खाते में चली गई। ये भाजपा के लिए बड़ा झटका है। क्योंकि राम मंदिर निर्माण के चलते माना जा रहा था कि सभी जातियों का वोट भाजपा को मिलेगा और वह अधिकतम सीटें जीत जाएगी। लेकिन जातीय और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण ने सपा के पक्ष में चला गया।

सकी थीं। बहरहाल, केंद्र की सत्ता में मोदी सरकार की हैट्रिक लग गई है। हालांकि, पिछले दो कार्यकाल में बीजेपी जहां अपने बूते पर सत्ता में थी तो वहीं इस बार उसे सहयोगियों पर निर्भर रहना होगा। पहले जो विपक्ष कमजोर था, अब वो पहले से ज्यादा

किन-किन राज्यों में हुआ बीजेपी को नुकसान?

लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को उप्र, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, बिहार आदि राज्यों में इस बार ज्यादा नुकसान हुआ है। खासकर उत्तरप्रदेश में तो बहुत ज्यादा ही नुकसान हुआ है। प्रदेश में बीजेपी दूसरे नंबर पर आ गई है जबकि 2014 और 2019 में यहां पर भाजपा ने सभी पार्टियों का सूपड़ा साफ कर दिया है। यही कारण है कि आज वह पूर्ण बहुमत भी हासिल नहीं कर सकी है। पिछले दो चुनावों में बीजेपी ने जो बढ़त हासिल की थी उसमें उप्र का बहुत बड़ा योगदान था। इसके अलावा बंगाल में भी बीजेपी काफी उम्मीद लगाई बैठी थी लेकिन ममता बैनर्जी ने आगे वह नतमस्तक साबित हुई। कई प्रयासों के बावजूद बंगाल में बीजेपी अपना दबदबा नहीं बना पा रही है। महाराष्ट्र में भी शिंदे गुट की शिवसेना को और न ही अजीत पवार की पार्टियों से बीजेपी को फायदा नहीं हुआ। खुद बीजेपी भी बहुत कमजोर होकर निकली। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को हरियाणा के अंदर कांग्रेस से जबरदस्त टक्कर मिली है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी में हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटें जीती थी। 2019 में बीजेपी को 58.02 प्रतिशत वोट मिले थे जबकि कांग्रेस को 28.42 प्रतिशत। यहां पर बीजेपी वैसा प्रदर्शन नहीं कर सकी जैसी उम्मीद की जा रही थी।

मजबूत हो गया है। इस बार लोकसभा चुनाव के बाद लोगों में चर्चा हो रही है कि इस नतीजे से सत्ता पक्ष भी खुश है और विपक्ष भी खुश है। कुछ लोग कह रहे हैं कि NDA तो इसलिए खुश है क्योंकि उसे तीसरी बार सत्ता मिली है लेकिन विपक्ष क्यों खुश है? विपक्ष के खुश होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि नरेन्द्र मोदी की लहर में विपक्ष धीरे-धीरे खत्म होता जा रहा था और विपक्ष को तोड़ा जा रहा था। विपक्ष उस भूमिका में भी नहीं था कि अपनी लड़ाई भी लड़ सके। लेकिन आज विपक्ष उस स्थिति में है कि वह अपनी लड़ाई विपक्ष में रहते हुए भी लड़ सकता है। सत्तापक्ष की हार यह है

इस बार लोकसभा चुनाव के बाद लोगों में चर्चा हो रही है कि इस नतीजे से सत्ता पक्ष भी खुश है और विपक्ष भी खुश है। कुछ लोग कह रहे हैं कि NDA तो इसलिए खुश है क्योंकि उसे तीसरी बार सत्ता मिली है लेकिन विपक्ष क्यों खुश है?

कि जहां से सबसे अधिक सीटें पिछले चुनाव में आई थीं, वह राज्य था उत्तर प्रदेश लेकिन वहां कड़ी पटखनी मिली। भाजपा ने 400 सीटों का विशाल लक्ष्य तय किया लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव जितनी सीटें भी लाने में असफल रही। सत्तापक्ष की जीत इस मायने में है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की हैट्रिक लगा रहे हैं। वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद ऐसे दूसरे नेता होंगे, जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं।

22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन देश में अलग ही माहौल नज़र आ रहा था। सिर्फ यूपी में ही नहीं पूरे देश में जश्न का माहौल था। दिन बड़ा भी

बीजेपी के लिए खतरा बना कम मतदान

लोकसभा चुनाव 2024 पूरे देश में सात चरणों में हुआ। इन सभी चरणों में सभी जगह पिछले चुनाव के मुकाबले मतदान का प्रतिशत काफी कम रहा। जिसका सीधा नुकसान बीजेपी को हुआ। यही वजह थी कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व हर बार मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर जोर देता रहा था। कम मतदान का असर भी चुनाव परिणाम में देखने का मिला है।

2024 के लोकसभा चुनावों के शुरूआती चरणों में देखी गई मतदान प्रतिशत में गिरावट का मतलब बीजेपी के लिए उलटफेर था। देश के ज्यादातर प्रदेश में कम मतदान हुआ है। 2019 के चुनाव में 67.6 प्रतिशत मतदान हुआ था। जबकि 2024 में लगभग 64 प्रतिशत मतदान हुआ है। जिसका एक प्रमुख कारण यही भी रहा कि लोगों को लगा कि मोदी की सरकार तो आ रही है मतदान करने का क्या मतलब। दूसरा कारण मतदान के समय सारे देश में भारी गर्मी हो रही थी। मतदाता घरों से निकलने में हिचक रहे थे।

अयोध्या की हार को कैसे पचा पायेगी बीजेपी

मोदी 3.0 के सत्ता में आने से पहले अब कई सीटों पर बीजेपी की हार को लेकर मंथन शुरूहो गया है। इन्हीं सीटों में से एक सीट है फैजाबाद की। आपको बता दें कि फैजाबाद लोकसभा सीट के तहत ही अयोध्या शहर आता है। वही अयोध्या जहां राम मंदिर का निर्माण कराने के साथ बीजेपी को उम्मीद थी कि वह इस बार इस सीट पर बड़े अंतर से जीत दर्ज करेगी। पर ऐसा हुआ नहीं। इस सीट से समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के उस समय के मौजूदा सांसद लल्लू सिंह को हराया है। सोशल मीडिया पर अब इस हार को लेकर तरह-तरह के कटाक्ष किए जा रहे हैं। बीजेपी यूपी के साथ-साथ समूचे उत्तर भारत में राम मंदिर और विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ी। लेकिन अगर खासतौर फैजाबाद की बात करें तो यहां पार्टी ने राम मंदिर को लेकर अयोध्या में जो विकास कार्य किए उसे मुद्दा बनाया। वहीं, समाजवादी पार्टी अपने पीडीए वाली रणनीति के साथ इस सीट पर जनता के बीच गई और जनता ने उन्हें अपना आशीर्वाद भी दिया। अब ऐसे में बीजेपी के अंदर ये एक बड़ी बहस बनती दिख रही है कि आखिर राम की नगरी में पार्टी को हार मिली कैसे। खासकर तब जब चुनाव से पहले राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर बीजेपी ने देश भर में अभियान भी चलाया था। बीजेपी को फैजाबाद लोकसभा सीट के तहत आने वाले पांच विधानसभा क्षेत्रों में से चार पर हार का सामना करना पड़ा है। अयोध्या भी इसी में से एक है। फैजाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी के हार के पीछे समाजवादी की रणनीति को भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने अपनी पीडीए (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) रणनीति को इस सीट पर भी मूर्तरूप दिया, यही वजह थी पार्टी ने अवधेश प्रसाद को यहां से टिकट दिया। अवधेश प्रसाद अनुसूचित जाति के पासी समुदाय से आते हैं। अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के लल्लू सिंह को 55 हजार वोट से हराया है। इस परिणाम में लल्लू सिंह के खिलाफ एंटी इनकंबेंसी का होना भी एक बड़ा फैक्टर साबित हुआ है। इसके साथ ही उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छबि भी प्रभावित हुई है। वैसे तो प्रदेश में बीजेपी कई सीटों पर हारी है लेकिन अयोध्या सीट बीजेपी को ज्यादा परेशान किया है।

था क्योंकि राम मंदिर बनने का सपना पूरा हो रहा था। उस दिन जो उत्साह नज़र आ रहा था उसी से भाजपा की ओर से यूपी समेत पूरे देश में ज़बरदस्त लहर बनाने की कोशिश की गई। लेकिन जनता में यह मुद्दा धीरे-धीरे धूमिल पड़ गया और भाजपा इसे

समझ नहीं पाई। भाजपा राम मंदिर को ही ट्रंप कार्ड मान रही थी जो चल नहीं सका। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, समाजवादी पार्टी को यूपी में 37 सीटें मिलना और अवध क्षेत्र में भाजपा की करारी हार होना। अमूमन लोगों में यह विमर्श हावी रहा कि राम मंदिर तो मिल गया लेकिन इसके अलावा और भी मुद्दे हैं।

चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा के एक-दो नेताओं ने ऐसे बयान दिया कि संविधान में बदलाव किए जा सकते हैं। हालांकि बाद में उन्होंने या पार्टी ने उन बयानों से किनारा भी कर लिया। लेकिन I.N.D.I.A. गठबंधन के नेताओं ने इसे अच्छे से भुनाया। राहुल गांधी अपने चुनाव प्रचार के दौरान जनसभाओं में संविधान दिखाते हुए नज़र आए। वह दोहराते रहे कि हम संविधान को

चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा के एक-दो नेताओं ने ऐसे बयान दिया कि संविधान में बदलाव किए जा सकते हैं। हालांकि बाद में उन्होंने या पार्टी ने उन बयानों से किनारा भी कर लिया। लेकिन I.N.D.I.A. गठबंधन के नेताओं ने इसे अच्छे से भुनाया। राहुल गांधी अपने चुनाव प्रचार के दौरान जनसभाओं में संविधान दिखाते हुए नज़र आए।

बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में भाजपा पिछड़े वोट बैंक को साधने में सफल रही थी, लेकिन इस बार पिछड़ा वर्ग ने भाजपा का साथ नहीं दिया। इस लोकसभा चुनाव में विपक्ष के लिए करो या मरो की स्थिति थी क्योंकि विपक्ष के नेताओं पर लगातार ED और CBI के छापे पड़ रहे थे। पिछले 5 साल विपक्ष के नेताओं के लिए काफी मुश्किलों भरे रहे। सदन से करीब 150 सांसदों का निलंबन, अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन का भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल जाना, राहुल गांधी को लोकसभा से बर्खास्त किया जाना विपक्ष के खिलाफ अहम फैसले रहे। इस घटनाक्रम की वजह इस चुनाव में विपक्ष अपनी जान झोंक दी। इसका असर चुनाव परिणामों में भी

लोकसभा चुनाव 2024 में किसानों के निकाला गुस्सा

लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे बीजेपी के लिए काफी चौंकाने वाले रहे हैं। चुनाव के नतीजों से बीजेपी को सबसे बड़ा झटका लगा है। बीजेपी अबकी बार 400 पार का स्लोगन लेकर चुनाव प्रचार कर रही थी। लेकिन जनता ने बीजेपी को 240 सीटों पर ही रोक दिया। बीजेपी की इस हार में देश के किसानों का गुस्सा भी सामने आ रहा है। खासकर पंजाब, हरियाणा के किसानों ने जमकर बीजेपी से अपनी भड़ास निकाली है। पंजाब में बीजेपी का खाता तक नहीं खुला है। वहीं हरियाणा में वह बेहतर स्थिति में नहीं रही। इसके अलावा अन्य प्रदेशों के किसानों ने भी बीजेपी का साथ नहीं दिया। किसानों के आंदोलन के कारण भी माहौल मोदी के विरोध में बना है। किसानों की मांगों को न मानकर बीजेपी ने अपना नुकसान किया है। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अकेले 303 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार बीजेपी को 63 सीटों का बड़ा नुकसान हुआ है। बीजेपी को भारी सीटों के नुकसान के पीछे के कारणों को लेकर पार्टी ने मंथन शुरू कर दिया है। बीजेपी को हुए भारी नुकसान के पीछे किसानों की मोदी सरकार से नाराजगी को सबसे बड़ी वजह के तौर पर देखा जा रहा है। कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी के खिलाफ देश में बड़ा आंदोलन हुआ था। कई दिनों तक दिल्ली में किसान धरने पर बैठ गए थे। हालांकि मोदी सरकार ने किसानों के गुस्से को देखते हुए कृषि कानून वापस ले लिए थे। लेकिन किसानों का गुस्सा शांत कराने में मोदी सरकार काफी हद तक असफल रही। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बीजेपी का वोट शेयर 2019 में 39.5 प्रतिशत से गिरकर अब 35 प्रतिशत हो गया है। इसके अलावा किसानों के विरोध के चलते बीजेपी को 40 सीटों के नुकसान का अनुमान भी लगाया जा रहा है।

बीजेपी की मजबूत उपस्थिति खासतौर पर शहरी केंद्रों में स्पष्ट थी। यह दिल्ली में स्पष्ट रूप से देखा गया, जहां पार्टी ने एक बार फिर बड़े अंतर से सभी 7 सीटें हासिल कीं। दूसरी ओर विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन ग्रामीण क्षेत्रों में दबदबा बनाते दिखा। गठबंधन के अहम दल कांग्रेस ने ग्रामीण क्षेत्रों में अपने वोट शेयर को 2019 में 17.1 प्रतिशत से थोड़ा बढ़ाकर 17.6 प्रतिशत देखा। वहीं समाजवादी पार्टी को ग्रामीण क्षेत्रों से 62.7 प्रतिशत समर्थन मिला, जिसने मोदी और योगी के नेतृत्व के डबल इंजन प्रभाव के बावजूद उत्तर प्रदेश में डंका बजा दिया।

देखने को मिला। I.N.D.I.A. गठबंधन जाति जनगणना को लेकर शुरू से मुखर रहा। बिहार में जातीय जनगणना की राजनीति तेजस्वी और नीतीश कुमार ने शुरू की। बिहार में जातीय जनगणना कराई गई। इसके बाद यह कार्ड अखिलेश और राहुल

भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने बदली राहुल गांधी की छवि

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के पहले दो महत्वपूर्ण यात्रायें भारत जोड़ो यात्रा और भारत न्याय यात्रा की थी। इन दोनों यात्राओ से राहुल गांधी की छवि को पूरी तरह से बदल दी है। साथ ही पूरे देश में कांग्रेस के प्रति एक सकारात्मक माहौल भी बना। वर्तमान में कांग्रेस की जो 99 सीटें लोकसभा चुनाव में आई हैं उनमें इन दोनों यात्राओं का महत्वपूर्ण योगदान है। हम जानते हैं कि 2014 और 2019 में कांग्रेस पूरे देश में काफी कमजोर हो गई थी। साथ ही प्रदेशों में भी कांग्रेस की सरकार कम थी। लेकिन 07 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा लगातार 150 दिन तक चली 3570 किमी यात्रा में कांग्रेस को जिंदा किया। इसके अलावा भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो 14 जनवरी 2024 को मणिपुर के थोउबल से शुरू हुई और यह पूर्व पश्चिम विस्तार को कवर करते हुये 20 मार्च 2024 को मुंबई में समाप्त हुई यात्रा से पूरे देश में कांग्रेस एक बार फिर फ्रंटफुट पर दिखाई दे रही है।

राहुल गांधी की राजनीतिक साख बढ़ी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास लौटा। इस यात्रा के दौरान उनके भीतर देश के अलग-अलग इलाकों के स्थानीय मुद्दों को लेकर समझ बनी। इस यात्रा के दौरान वह हज़ारों किसानों, मज़दूरों, महिलाओं, युवाओं, और आम लोगों से मिले। उनके महंगाई और बेरोज़गारी जैसे मुद्दों को समझे और अपनी जनसभाओं में लोगों को इनके बारे में समझाने में सफल रहे। पिछले लोकसभा चुनाव में 52 सीटें पाने वाली कांग्रेस ने 99 सीटें हासिल की।

गांधी दोनों ने आक्रामक तरीके से खेला। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में सफलता भी मिली। हालांकि चुनाव के बीच में नरेन्द्र मोदी ने विपक्ष के जातीय जनगणना के मुद्दे पर काउंटर करने की जरूर कोशिश की। उन्होंने कहा कि विपक्ष पिछड़ों के आरक्षण को मुस्लिमों में बांटना चाहती है लेकिन कहीं न कहीं लगातार इस मुद्दे पर टिके रहने का लाभ विपक्ष को मिला।

मोदी का गारंटी पर नहीं लगी मुहर

बीजेपी के संकल्प पत्र में हर वादे पर मोदी की गारंटी की मुहर थी और साफ़ था पार्टी अपने सबसे बड़े नेता को चुनावी चेहरा बनाकर प्रोजेक्ट कर रही है। यानी 2013 में जब से मोदी पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने थे, तब से अब तक कुछ नहीं बदला था। इस दौरान पार्टी न सिर्फ केंद्र में आसीन रही बल्कि भाजपा ने दूसरे राज्यों पर भी अपनी पकड़ मज़बूत की लेकिन इस चुनाव में मोदी की गारंटी का मनचाहा असर नहीं हुआ। भाजपा की रणनीति शुरू से आखिर तक अपने प्रधानमंत्री पर ही पूरा दांव लगाने की थी। इसमें तो कोई शक नहीं था कि मोदी फिलहाल भारत के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और भाजपा ने इसी बात को अपना ट्रंप-कार्ड बना रखा था। इस पार्टी का इतिहास बताता है कि किसी भी चुनाव में सिर्फ एड्ड व्यक्तिके इर्द-गिर्द इतनी व्यापक चुनावी कैंपेन नहीं हुई थी जितनी 2024 में हुई। दरअसल नरेंद्र मोदी का प्रोजेक्शन उससे भी बड़ा किया गया जैसा इंदिरा गांधी का 1971 कैंपेन में किया गया था। दरअसल भाजपा का आंकलन कुछ नतीजों पर आधारित था। 2014 के आम चुनाव से पहले भाजपा और उसके गठबंधन वाली सरकारों की तादाद सात थी जबकि 2024 चुनावों के ठीक पहले देश के 16 राज्यों में भाजपा की अपनी सरकार थी और चार राज्यों में गठबंधन सरकारें, यानी कुल आंकड़ा 20 का है। जाहिर है, मोदी फैक्टर का बड़ा रोल रहा था पार्टी को सत्ता में बनाए रखने में। लेकिन ताजा नतीजे इस ओर भी इशारा कर रहे हैं कि सभी को मोदी की गारंटी में पूर्ण विश्वास नहीं था वरना 2014 के चुनाव में भाजपा को 282 सीटें, 2019 के लोकसभा चुनाव में 303 सीटें जिताने वाले नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा को 2024 बहुमत से पहले ही रुक गई।

विपक्षी दल भी इसमें पीछे नहीं रहे। मुफ्त नौकरियों और पॉकेट मनी के वादों के साथ-साथ यह लगातार कहा जा रहा था कि मोदी को वोट देकर दोबारा सत्ता में लाना खतरनाक होगा क्योंकि वह लोकतंत्र और संविधान को खत्म कर देंगे। इस चुनाव में नरेन्द्र मोदी की अगुआई में बीजेपी के सामने चुनौतियां कहीं अधिक थीं। स्थानीय सांसद के खिलाफ नाराजगी थी। कहीं न कहीं दस

नीतीश और चंद्रबाबू नायडू ने साथ छोड़ा तो क्या होगा?

अब अगर मान लें कि नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए छोड़कर इंडिया में शामिल होते हैं तो उनके 12 सांसदों के हटने से एनडीए की संख्या घटकर 280 हो जाएगी। यानी, एनडीए के पास उस स्थिति में भी सरकार बनाने के लिए पर्याप्त संख्या बल रहेगा। सोशल मीडिया पर एक और कयासबाजी चल रही है कि चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी को भी विपक्ष अपने साथ लाने की कोशिश कर सकता है। अब अगर ये भी मान लें कि नीतीश कुमार के बाद चंद्रबाबू नायडू एनडीए छोड़ सकते हैं तो उनके 16 सासंदों को हटाने के बाद एनडीए की सीटों की संख्या घटकर 264 हो जाएगी। यानी मैजिक नंबर से एनडीए 08 सीट पीछे हो जाएगी। इस स्थिति में जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी के 04 सांसदों और 07 निर्दलीयों की मदद से एनडीए के सरकार गठन की संभावना बनी रहेगी। क्योंकि, टीडीपी अगर एनडीए से अलग होती तो वाईएसआरसीपी के साथ आने की गुंजाइश बन सकती है।

सालों के शासन के बाद मोदी सरकार के कामकाज को लेकर मुखर सवाल भी थे लेकिन नरेन्द्र मोदी के राष्ट्रवाद नैरेटिव ने इन सवालों को न्यूट्रल कर दिया। इसमें महंगाई, बेरोजगारी जैसे मसले को काउंटर करने की कोशिश की गई और संदेश दिया गया कि इन समस्याओं से निजात के लिए नरेन्द्र मोदी ही अभी सबसे बेहतर विकल्प हैं।

तमाम कोशिशों के बावजूद दक्षिण फतह नहीं कर पा रही बीजेपी

पिछले 10 सालों से भाजपा दक्षिण भारत को फतह करने की तमाम तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) के नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन ने राज्य की सभी 39 सीटें जीती है। गठबंधन ने केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की एकमात्र सीट पर भी जीत दर्ज की है।

पिछले 10 सालों से भाजपा दक्षिण भारत को फतह करने की तमाम तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) के नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन ने राज्य की सभी 39 सीटें जीती है। गठबंधन ने केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की एकमात्र सीट पर भी जीत दर्ज की है। कांग्रेस ने तमिलनाडु और पुडुचेरी में 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। इन सभी दस सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली है।

चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कई बार तमिलनाडु पहुंचे। लेकिन इसके बाद भी बीजेपी राज्य में एक सीट भी नहीं जीत सकी। हालांकि बीजेपी राज्य के 10 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही। पार्टी और उसके बड़े नेताओं के काफी प्रयास के बाद भी बीजेपी राज्य में छाप छोड़ने में सफल नहीं रही। बीजेपी के पूर्व सहयोगी अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) ने राज्य के करीब 29 सीटों पर दूसरा स्थान प्राप्त किया है। वहीं, दूसरे लोकसभा सीटों पर पार्टी तीसरे और चौथे स्थान पर रही।

दक्षिण में क्यों हार जाती है बीजेपी?

INDIA गठबंधन की तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और तेलंगाना में सरकार है। पूरे दक्षिण भारत को देखा जाए, बीजेपी बनाम कांग्रेस तो सात राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश हैं।। ये सब मिलाकर लोकसभा में कुल 131 सांसद भेजते हैं। साल 2019 में हुए आम चुनाव में कांग्रेस ने इनमें से पांच राज्यों- केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और तेलंगाना में 28 सीटें जीती थीं। दूसरी ओर बीजेपी को केवल कर्नाटक और तेलंगाना में जीत मिली थी। बावजूद इसके कुल सीटों के मामले में दक्षिण भारत में वह कांग्रेस से एक सीट ज़्यादा थी। वैसे 2019 में साउथ में वोट प्रतिशत की बात करें तो कांग्रेस ज़्यादा मजबूत दिखी। केवल एक अपवाद कर्नाटक था, जहां तब कांग्रेस-जेडीएस की सरकार थी और बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में 50 फीसदी से ज्यादा वोट हासिल कर लिए। हालांकि चुनाव के बाद राज्य की गठबंधन सरकार गिर गई। केरल की बात करें तो यहां लेफ्ट और कांग्रेस के बीच पारंपरिक प्रतिद्वंद्विता रही है। बीजेपी यहां अब अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश में लगी है।

INDIA गठबंधन की तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और तेलंगाना में सरकार है। पूरे दक्षिण भारत को देखा जाए, बीजेपी बनाम कांग्रेस तो सात राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश हैं।। ये सब मिलाकर लोकसभा में कुल 131 सांसद भेजते हैं।

ऐसे समझिए सीटों का गणित

एनडीए की 292 सीटों में बीजेपी की 240, टीडीपी की 16, जेडीयू की 12, शिवसेना (शिंदे) की 07, एलजेपी (रामविलास) की 05, जेडीएस की 02, आरएलडी की 02, जेएसपी की 02, एजीपी की 01, यूपीपीएल की 01 एजेएसयूपी की 01, एनसीपी की 01, हम की 01 और अपना दल की 01 सीट शामिल है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया अब जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार को अपने पाले में लाने की कोशिश कर सकता है। चूंकि नीतीश कुमार इससे पहले भी कई बार पाला बदल चुके हैं। इसलिए ऐसे में ये चर्चा और ज्यादा हलचल मचा रही है।

क्या भविष्य में इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है?

अब विपक्षी गठबंधन इंडिया पर आते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों में इंडिया को 234 सीटें मिली हैं। इनमें कांग्रेस की 99, समाजवादी पार्टी की 37, तृणमूल कांग्रेस की 29, डीएमके की 22, शिवसेना (यूबीटी) की 09, एनसीपी (शरद पवार) की 08, आरजेडी की 04, सीपीएम की 04, आईयूएमएल की 03, आम आदमी पार्टी की 03, जेएमएम की 03, जेकेएनसी की 02, वीसीके की 02, सीपीआई की 02, सीपीआई (एमएल) की 02 और केसी, आरएलटीपी, बीएडीवीपी, एमडीएमके और आरएसपी की 01 सीट शामिल है। इस तरह विपक्षी गठबंधन सरकार बनाने के संख्या बल से 38 सीटें पीछे हैं।

दक्षिण के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के व्यापक वोट शेयर से पता चलता है कि इस क्षेत्र में कांग्रेस से बीजेपी कमजोर है। हालांकि 2019 में उसने अधिक सीटें जीतीं। दक्षिणी राज्यों में गठबंधन का हिस्सा होने पर कांग्रेस अधिक मजबूत दिखती है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु में जहां उसका द्रमुक के साथ गठबंधन है। इस सियासी दोस्ती ने 39 में से 38 लोकसभा सीटें जीतीं। केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 2019 में 20 में से 19 सीटों पर जीत हासिल की थी। अगर वर्तमान INDIA गठबंधन के सहयोगियों ने 2019 का चुनाव एक साथ लड़ा होता, तो उसके हिस्से दक्षिण की 131 में से 63 सीटें आई होतीं। वोट शेयर के मामले में भी INDIA ने NDA से बेहतर प्रदर्शन किया होता।

अगर वर्तमान INDIA गठबंधन के सहयोगियों ने 2019 का चुनाव एक साथ लड़ा होता, तो उसके हिस्से दक्षिण की 131 में से 63 सीटें आई होतीं। वोट शेयर के मामले में भी INDIA ने NDA से बेहतर प्रदर्शन किया होता।

अब बात करें तमिलनाडु की तो यहां बीजेपी अपने दम पर बढ़त बनाने में विफल रही है। 2014 में उसने एक सीट जीती, लेकिन 2019 में एआईएडीएमके के साथ गठबंधन करने के बावजूद अपना खाता

कहां से आ सकती हैं बहुमत के लिए 38 सीटें

अब अगर विपक्षी गठबंधन इंडिया केंद्र में सरकार बनाने की तरफ कदम बढ़ाता है, तो सबसे पहले उसे इन 38 सीटों का इंतजाम करना होगा। मान लीजिए कि पप्पू यादव को छोड़कर 06 निर्दलीय और आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर का समर्थन विपक्ष को मिलता है, तो उसकी संख्या 234 से बढ़कर 241 हो जाएगी। यानी अभी भी बहुमत के आंकड़े से 31 सीट दूर। यहां आकर अगर उपर लिखे समीकरण के हिसाब से गिनती बिठाएं और नीतीश के साथ चंद्रबाबू नायडू को भी जोड़ें तो दोनों के सांसदों की संख्या मिलने के बाद विपक्ष के पास 269 सीटें हो जाएंगी। ये संख्या 272 के आंकड़े से अभी भी 03 सीट कम है। अब इन तीनों सीटों के लिए विपक्ष को अपना दल (1) और आरएलडी (2) को साथ लेना होगा, जिसके बाद उसके पास बहुमत का आंकड़ा बन जाएगा। लेकिन, इस स्थिति में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि जोड़-तोड़ की सरकार में प्रधानमंत्री का पद किसे मिलेगा ? खैर, देश में एक बार फिर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। आज संसद के सेंट्रल हॉल में एनडीए के सभी घटक दलों ने नरेंद्र मोदी को अपना संसदीय दल का नेता चुना। राजनाथ सिंह ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा था, जिस पर सभी दलों के नेताओं ने अपनी सहमति जताई।

खोलने में असफल रही। लेकिन, बीजेपी ने तब से अपने प्रयास बढ़ा दिए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी तमिल संस्कृति को लेकर मुखर रहे हैं। केंद्र सरकार ने काशी-तमिल संगमम जैसे कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मोदी ने पिछले साल नए संसद भवन में जो राजदंड स्थापित किया, उसे उन्हें तमिलनाडु के पुजारियों ने दिया था। लेकिन, क्या इन प्रयासों से 2024 में वोट मिला?

2014 में बीजेपी ने तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था। 2019 में वह अकेले दम मैदान में उतरी। 2024 में विधानसभा और लोकसभा में बीजेपी और टीडीपी ने एक साथ चुनाव लड़ा। जिसका दोनों को लाभ

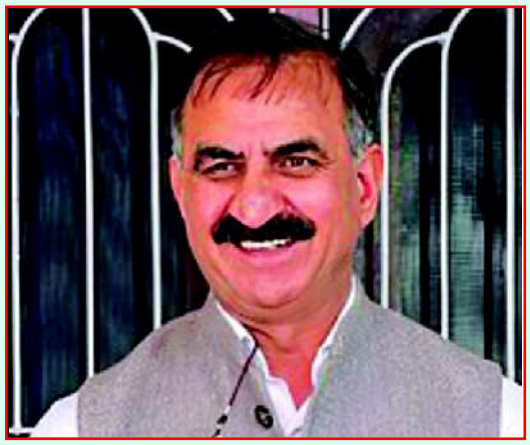

हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने बचाई सरकार

लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बीच हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस अपनी सरकार बचाने में कामयाब रही है। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीटों के साथ ही विधानसभा की 06 सीटों पर भी उपचुनाव हुआ था। अपनी सरकार बचाने के लिए इन 06 सीटों में से कांग्रेस को कम से कम एक सीट पर जीत हासिल करना जरूरी था। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की छह सीटों पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल करने वाले कांग्रेस के चार नए विधायक कांग्रेस सरकार के लिए सुरक्षा कवच का काम करेंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में अब कांग्रेस के सदस्यों की संख्या 34 से बढ़कर 38 हो गई है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में तीन निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे तीन जून को ही स्वीकार हुए हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में फिलहाल सदस्यों की संख्या 65 है और बहुमत का आंकड़ा 33 है। ऐसे में 38 सदस्यों के साथ कांग्रेस पूरी तरह सुरक्षित हो चुकी है।

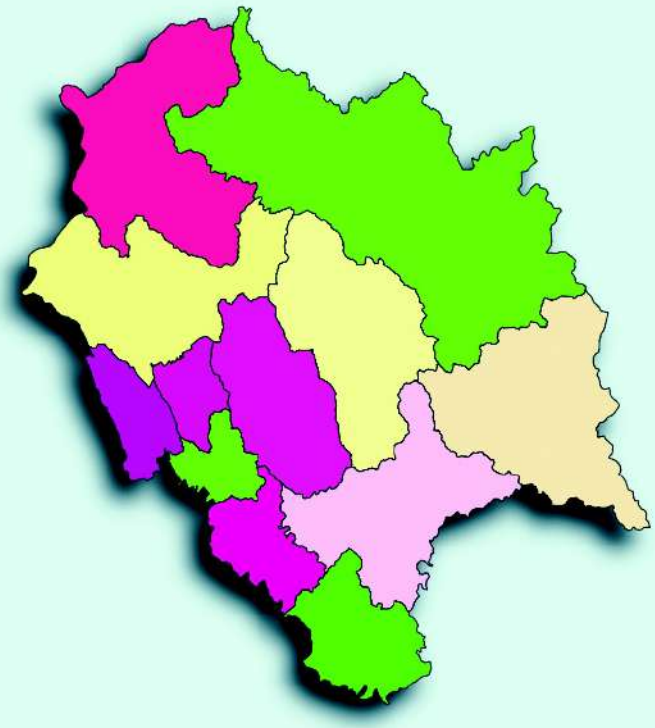

हुआ। आंध्र प्रदेश में टीडीपी की सरकार बन गई है और उसके 16 सांसद भी चुनाव जीतकर आये हैं। 2024 में टीडीपी मोदी सरकार में एक मजबूत और सबसे बड़ा सहयोगी दल है और सरकार का हिस्सा भी है। जब तेलंगाना को अलग राज्य बनाया गया, तो मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने आंध्र प्रदेश को विशेष श्रेणी का दर्जा देने का वादा किया। लेकिन 2014 की जीत के बाद मोदी सरकार ने विशेष श्रेणी के बजाय विशेष पैकेज की पेशकश की। यह एक प्रमुख मुद्दा था, जिस पर चंद्रबाबू नायडू ने 2018 में एनडीए से नाता तोड़ लिया। कर्नाटक को देखा जाए, तो 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। उसके 135 विधायक जीते और 43 फीसदी वोट शेयर रहा। वहीं, बीजेपी का वोट शेयर 36

राजस्थान से बीजेपी के लिए बुरी खबर

लोकसभा 2024 के इस चुनाव में राजस्थान के नतीजों में भाजपा को 14 बनाम 11 के आंकड़े ने सत्तारूढ़ भाजपा और उसके समर्थकों को बहुत बेचैन कर दिया है। भाजपा के किसी नेता ने सपने में भी नहीं सोचा था कि राजस्थान के नतीजे इस तरह के रहने वाले हैं। ख़ासकर साल 2019 में अपने एक समर्थक के साथ सभी 25 लोकसभा सीटों पर परचम फहराने वाली भाजपा के लिए इन नतीजों को पचा पाना आसान नहीं है। चुनावों की प्रक्रिया शुरू होने से पहले सभी लोकसभा क्षेत्रों में से ऐसे संकेत आ रहे थे कि मानो मतदाताओं का बड़ा वर्ग कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा से कोई प्यारा नहीं है; लेकिन नतीजे आए तो ऐसा लगा कि कुछ ही दिन में खंडित जनादेश देने वाले मतदाता ने कह दिया कि तेरा साथ इतना भी गवारा नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी ने राजस्थान की सभी 25 सीटें जीती थी। राजस्थान में तीन सीटें इस बार कांग्रेस ने समझौते में सहयोगी दलों को दी और इन तीनों पर उन दलों के उम्मीदवार जीते हैं।

फीसदी रहा और केवल 66 विधायक जीत पाए। कर्नाटक में विधानसभा चुनावों में बीजेपी को कभी कांग्रेस से ज्यादा वोट नहीं मिले। 1999 के इलेक्शन को छोड़कर, 1998 से लेकर आम चुनावों में सीटों के मामले में बीजेपी कांग्रेस से आगे रही है।

इन मुद्दों पर लड़ा N.D.A.

■ **जो राम को लाए हैं, उन्हें लाना है**

इस साल 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण स्थापना की गई। इस घटना का व्यापक असर हुआ। जमीन स्तर पर इसका सियासी असर दिखा। बीजेपी ने चुनाव में नारा भी दिया, जो राम को लाए हैं, उन्हें फिर से लाना है। खुद पीएम मोदी ने इस बार चुनावी रैलियों में इस मुद्दे पर जनता से कनेक्ट करने की कोशिश की। इसका कुछ असर दिखा लेकिन अंतिम परिणाम ने साबित किया कि यह पूरी तरह काफी नहीं था।

■ **जिसने राशन दिया, वोट भी उसी को**

चुनाव में मोदी सरकार की मुफ्त राशन योजना ने अपना काम किया। पिछले कुछ चुनावों से मुफ्त राशन का व्यापक असर देखा गया है। इस चुनाव में भी ग्राउंड पर

महंगाई और बेरोज़गारी को मुद्दा बनाने में सफल रहा विपक्ष

बेरोज़गारी और महंगाई का मुद्दा जनता में था लेकिन यह हाशिए पर चला गया था। राम मंदिर के बहाने भाजपा इस बार का चुनाव हिंदुत्व के अजेंडे पर लड़ने में लगी रही। विपक्ष बेरोज़गारी और महंगाई के मुद्दे पर टिका रहा। लेकिन भाजपा इसकी कोई काट पेश नहीं कर पाई। हर बार ऐसा होता था कि चुनावी मैदान में भाजपा हिंदुत्व की पिच तैयारी करती थी और विपक्ष को न चाह कर भी इसी पिच पर खेलना पड़ता था। इस बार I.N.D.I.A. गठबंधन ने बेराज़गारी और महंगाई का चुनावी पिच तैयार की।

लोगों के बीच इस स्कीम का जादू था और कहीं न कहीं गरीब वोटरों के बीच नरेन्द्र मोदी के प्रति कृतज्ञता का अहसास था। कांग्रेस को इस स्कीम का लोगों से कनेक्ट का अहसास चुनाव के बीच देर से अंदाजा लगा। ऐसे में पार्टी ने चुनाव के बीच में एनडीए सरकार के पांच किलो मुफ्त राशन की जगह दस किलो राशन मुफ्त देने का वादा किया।

इन मुद्दों पर टिका रहा I.N.D.I.A.

■ संविधान को बचाना है

नरेन्द्र मोदी ने इस चुनाव में अबकी बार 400 पार का नारा दिया था। ओपेनियन पोल में ऐसा लगा भी कि ऐसा मुमकिन है लेकिन इंडिया गठबंधन ने आपदा में अवसर देखा। वे जनता के बीच गए और कहा कि बीजेपी को 400 सीट इसलिए चाहिए कि वे संविधान को बदलना चाहते हैं। जमीन पर इसका असर हुआ। लोगों ने विपक्ष के इस तर्क को कहीं न कहीं स्वीकार किया कि बड़ी जीत से मौजूदा व्यवस्था बदल जाएगी।

■ जाति जनगणना

इंडिया गठबंधन ने जाति जनगणना का कार्ड आक्रामक रूप से खेला। वे इसके बहाने ओबीसी तक पहुंचने में सफल रहे। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में सफलता भी मिली। हालांकि चुनाव के बीच में नरेन्द्र मोदी ने विपक्ष के इस अजेंडे को काउंटर करने की जरूर कोशिश की कि विपक्ष पिछड़ों के आरक्षण को मुस्लिमों में बांटना चाहती है लेकिन कहीं न कहीं लगातार इस मुद्दे पर टिके रहने का लाभ मिला और बीजेपी के मजबूत ओबीसी वोट में सेंध लगाने में सफल हुई।

■ युवाओं को नौकरी, महिलाओं को पगार

युवाओं को 30 लाख सरकारी नौकरी और महिलाओं को हर साल एक लाख की पगार, ये दो ऐसे चुनावी वादे थे जिससे इंडिया गठबंधन ने एनडीए के युवा और महिला वोट में सेंधमारी की। विपक्ष अपने इन्हीं दो मुद्दों पर पूरी तरह केंद्रित रहा। इसके अलावा अग्निवीर योजना को रद्द करने जैसे फैसले का प्रचार किया। इसका लाभ उन्हें चुनाव में मिला।

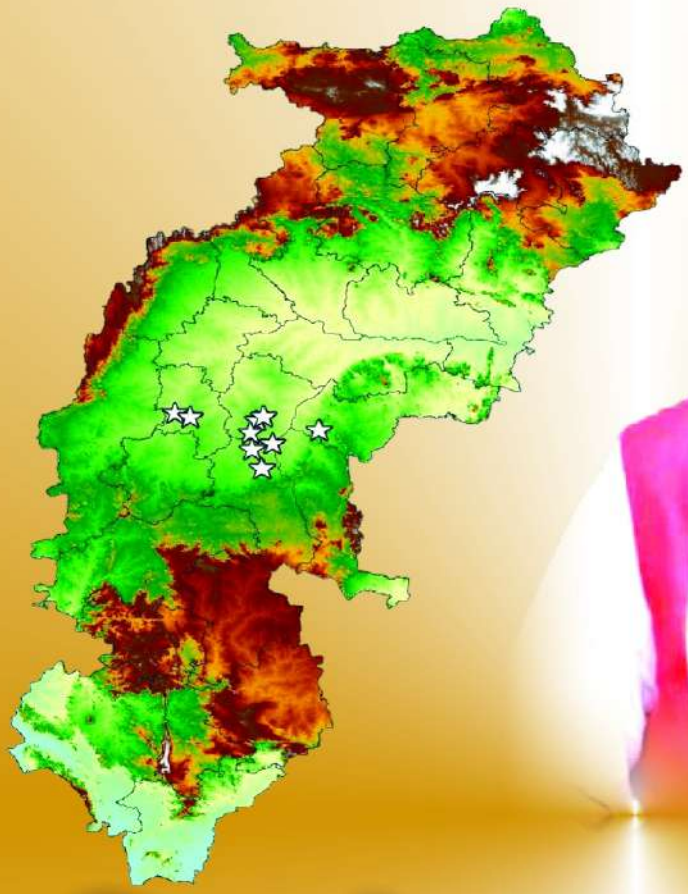

विष्णुदेव साय सरकार के सुशासन के 06 माह

किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण के लिए बढ़े कदम

छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार ने सुशासन के छह महीने पूरे कर लिए हैं। सुशासन के प्रारंभिक 06 माह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने कार्यों से दर्शा दिया है कि वह प्रदेश के विकास और लोगों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। सबके साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के तर्ज पर सरकार ने चुनावी समय में किये गये अपने वादों पर अमल करना प्रारंभ कर दिया है। लोगों के भरोसे और इच्छा के अनुरूप कई कल्याणकारी योजनाओं का शुरूकिया गया है। इसके साथ ही निवर्तमान भूपेश बघेल सरकार के दौरान प्रदेश ने विकास की रफ्तार जो ठप्प पड़ गई थी उसको भी गति प्रदान की है। भूपेश सरकार के कुशासन में लोगों ने जो ज्यादतियां झेली थी उससे से भी राहत के कार्य किये जा रहे हैं। प्रशासनिक स्तर पर जो तानाशाही की जा रही थी वह भी सुशासन में बदल रही हैं। इस छोटी अवधि में सरकार ने डेढ़ दर्जन से अधिक ऐसे फैसले किए, जिससे छत्तीसगढ़ के किसान, युवा और महिलाओं को लाभ पहुंचा या फिर राहत मिली। मुख्यमंत्री विष्णुदेव के नेतृत्व में सुशासन के ट्रैक पर छत्तीसगढ़ ने फिर से विकास की रफ्तार पकड़ ली है। बीते छह माह पर नजर डाले तो साय सरकार ने किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए बहुत कम समय में ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए वर्ष 2047 तक विकसित-छत्तीसगढ़ का निर्माण के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए विजन डाक्यूमेंट तैयार करने का काम भी शुरू कर दिया गया है। विधानसभा चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ के लोगों को गारंटी दी थी कि छत्तीसगढ़ में लोगों के जीवन में खुशहाली और समृद्धि के लिए सुशासन की स्थापना की जाएगी। इसे ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक अलग सुशासन और अभिसरण विभाग का गठन किया है। यह विभाग कल्याणकारी नीतियों के सफल क्रियान्वयन, उपलब्ध संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग और जन समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए काम कर रहा है। सभी विभागों को सुशासन के लिए अधिक से अधिक आईटी का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए हैं।

विजया पाठक

छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने आवासहीन और जरूरतमंद 18 लाख परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति, 13 लाख से अधिक किसानों को धान की बोनस राशि, 3100 रु पए प्रति क्विंटल की दर से और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदी, महतारी वंदन योजना में 70 लाख से अधिक गरीब परिवारों की महिलाओं को हर माह एक-एक हजार रू पए देने जैसे अनेक निर्णयों पर क्रियान्वयन किया है। राज्य के माओवाद

प्रभावित क्षेत्रों में माओवाद उन्मूलन के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। इन क्षेत्रों में लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नियद नेल्लानार योजना शुरूकी गई है। महतारी वंदन योजना, कृषक उन्नति योजना, रामलला दर्शन योजना, उद्यम क्रांति योजना जैसी कई अभिनव योजनाओं की शुरूआत हुई है। लोकतंत्र सेनानियों (मीसा बंदियों) की सम्मान निधि फिर से शुरू कर दी गई है।

06 माह की महत्वपूर्ण उपलब्धियां

पहली कैबिनेट में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सरकार बनने के दूसरे ही दिन कैबिनेट की बैठक आयोजित कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी के अनुरूप 18 लाख 12 हजार 743 जरूरतमंद परिवारों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने स्वीकृति दे दी। इसके लिए 12 हजार 168 करोड़ रूपए का बजट

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटियों पर प्राथमिकता से का शुरू

समाज के लिए कल्याण के लिए प्रतिबद्ध सरकार

प्रावधान किया गया है। अब इनमें भी गति पकड़ ली है।

13 लाख किसानों को धान का बोनस

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के किसानों को गारंटी दी थी कि सरकार बनने पर राज्य के किसानों को 02 साल का बकाया धान बोनस देंगे। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस, सुशासन दिवस पर छत्तीसगढ़ सरकार ने 13 लाख किसानों के बैंक खातों में 3716 करोड़ रूपए का बकाया धान बोनस अंतरित कर इस गारंटी को भी पूरा किया है।

3100 रूपए में धान की खरीदी

साय सरकार ने 3100 रूपए प्रति क्विंटल की दर से और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदने की गारंटी को पूरा करते हुए 32 हजार करोड़ रूपए के समर्थन मूल्य की राशि का तत्काल भुगतान किसानों को किया और फिर 12 जनवरी को 24 लाख 75 हजार किसानों को कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत अंतर की राशि 13 हजार 320 करोड़ रूपए की राशि

अंतरित की है। इस साल खरीफ सीजन में राज्य में 145 लाख मीट्रिक टन धान की रिकॉर्ड खरीदी हुई है।

70 लाख महिलाओं का वंदन

महतारी वंदन योजना के अंतर्गत महिलाओं के बैंक खातों में राशि अंतरण का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल उपस्थिति में 10 मार्च 2024 को हुआ। इस योजना के अंतर्गत राज्य की पात्र महिलाओं को प्रति माह एक-एक हजार रूपए की सहायता राशि दी जा रही है। योजना का लाभ 70 लाख से अधिक महिलाओं को मिल रहा है। अब तक इस योजना की चार माह की राशि जारी की जा चुकी है। पिछली सरकार ने महिला स्व सहायता समूहों से रेडी टू ईट का काम छीन लिया था। छत्तीसगढ़ सरकार ने अब फिर से उन्हें यह काम सौंप दिया है।

श्री रामलला दर्शन योजना

छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं को अयोध्या में विराजमान श्री रामलला के दर्शन हेतु निःशुल्क आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य में श्री रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना संचालित की जा रही है। शासकीय व्यय में अब तक हजारों दर्शनार्थी श्री रामलला के दर्शन के

लिए अयोध्या भेजे जा चुके हैं।

गरीबों के लिए मुफ्त राशन

छत्तीसगढ़ सरकार ने 68 लाख गरीब परिवारों को 05 साल तक मुफ्त राशन देने का निर्णय लिया है। इसके लिए बजट में 34 सौ करोड़ रूपए का प्रावधान है। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष 10 हजार रूपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए भी बजट में 500 करोड़ रूपए का प्रावधान कर दिया गया है।

तेन्दूपत्ता संग्रहण दर अब 5500 रूपए

राज्य में तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक दर 4000 रु पए प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर अब 5500 रु पए प्रति मानक बोरा कर दी गई है। चालू तेंदूपत्ता सीजन से ही 12 लाख 50 हजार तेंदूपत्ता संग्राहकों को योजना का लाभ मिल रहा है। संग्राहकों के लिए राज्य सरकार द्वारा चरण पादुका योजना भी शुरू की जाएगी, साथ ही उन्हें बोनस का लाभ भी दिया जाएगा।

भर्ती में युवाओं को पांच वर्ष की छूट

युवाओं की बेहतरी के लिए राज्य सरकार ने अहम निर्णय लेते हुए पुलिस विभाग सहित विभिन्न शासकीय भर्तियों में युवाओं को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट का निर्णय लिया है। अभ्यर्थियों को 31 दिसंबर 2028 तक आयु

सीमा में 05 वर्ष छूट का लाभ मिलेगा।

यूपीएससी की तर्ज पर होगी पीएससी

यूपीएससी की तर्ज पर छत्तीसगढ़ पीएससी परीक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए यूपीएससी के पूर्व चेयरमेन प्रदीप कुमार जोशी की अध्यक्षता में आयोग का गठन कर दिया गया है। पीएससी की घोटाले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है।

पांच शक्तिपीठों का होगा विकास

राज्य की 05 शक्तिपीठों के विकास के लिए बजट में 5 करोड़ रु पए का प्रावधान कर दिया गया है। शक्तिपीठों के विकास के लिए चारधाम की तर्ज पर 1000 किलोमीटर की परियोजना शुरू की जाएगी। ग्रामीण घरों को नल से जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत 4500 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

युवाओं के लिए उद्यम क्रांति योजना

राज्य में युवा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए उद्यम क्रांति योजना शुरू करते हुए

बजट प्रावधान भी कर दिया है। इस योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी पर ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की गई है।

अधोसंरचना और कनेक्टीविटी पर जोर

राज्य में सड़क, रेल और हवाई यातायात की सुविधाओं के विस्तार का काम भी शुरू हो चुका है। बिलासपुर और

जगदलपुर से नयी उड़ानें शुरू हो चुकी हैं। जशपुर और बलरामपुर हवाई पट्टी के विस्तार के लिए बजट में प्रावधान कर दिया गया है। अंबिकापुर और जगदलपुर हवाई अड्डों में भी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।

राजिम कुम्भ कल्प की पुनः शुरूआत

राज्य की संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए राजिम मेले का आयोजन पुनः उसके व्यापक स्वरूप में राजिम कुंभ कल्प के रूप में शुरू कर दिया गया है। बस्तर में प्राचीन काल से चले आ रहे अनेक ऐतिहासिक मेलों को भी शासकीय संरक्षण और सहायता दी जा रही है।

रायपुर में आईटी हब बनाने का काम शुरू

रायपुर को आईटी हब बनाने का काम शुरू हो गया है। हाल ही में 2 आईटी कंपनियों के साथ एमओयू हुआ है, उन्हें फर्नीस्ड बिल्डअप एरिया भी उपलब्ध करा दिया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार नवा रायपुर को बेंगलुरू की तर्ज पर आईटी हब के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य कर रही है।

शहीद वीर नारायण सिंह स्वास्थ्य योजना

राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार

विकास ने पकड़ी रफ्तार, हर वर्ग की योजनाओं पर अमल शुरू

के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ ही शहीद वीरनारायण सिंह स्वास्थ्य योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है। राज्य के दो बड़े मेडिकल कॉलेज अस्पतालों, मेडिकल कॉलेज अस्पताल रायपुर और छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बिलासपुर (सिम्स) में भवन के विस्तार और सुविधाओं के विकास का काम शुरू कर दिया गया है।

आईआईटी की तर्ज पर प्रौद्योगिकी संस्थान

राज्य में उच्च शिक्षा विभाग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का निर्णय लिया है। आईआईटी की तर्ज पर राज्य के जशपुर, बस्तर, कबीरधाम, रायपुर और रायगढ़ में प्रौद्योगिकी संस्थानों का निर्माण किया जाएगा। राज्य में छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा मिशन की स्थापना की जाएगी।

राज्य-राजधानी क्षेत्र का विकास (एससीआर)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विकास योजना की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर) के विकास के लिए विस्तृत योजना बनाने का प्रावधान किया गया है। इससे राज्य में शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा।

इंडस्ट्रियल कॉरिडोर

राष्ट्रीय राजमार्गों के आसपास औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कोरबा-बिलासपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। इन्वेस्ट इंडिया की तर्ज पर इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ आयोजित करने के लिए बजट में पांच करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। खनिजों के परिवहन में पारदर्शिता के लिए खनिज परिवहन हेतु ऑनलाइन ई-ट्रांजिट पास जारी करने की व्यवस्था पुनः प्रारंभ की गई है। इससे राज्य को मिलने वाले राजस्व में वृद्धि होगी।

आर्थिक सलाहकार परिषद

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने के लिए विशेषज्ञ संस्थाओं से परामर्श करने तथा देश और दुनिया में चल रहे बेस्ट प्रैक्टिस को राज्य की परिस्थिति के अनुरूप लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन करने का निर्णय लिया गया है।

छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के स्थान पर कौन?

विजया पाठक

छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रीमंडल में शामिल प्रदेश के कददावर नेता कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल हाल ही में लोकसभा का चुनाव जीतकर सांसद बन गये हैं। ऐसी स्थिति में अग्रवाल को मंत्रीपद छोड़ना होगा। लेकिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सामने अब सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि बृजमोहन अग्रवाल के स्थान पर किसे मंत्री बनाया जाये। फिलहाल चर्चाओं का जो दौर चल रहा है उसमें कई नाम सामने आ रहे हैं। इनमें दो नाम सबसे ज्यादा चर्चित हो रहे हैं। वह दो नाम हैं पूर्व में मंत्री रहे अजय चंद्राकर और अमर अग्रवाल का। इन दोनों नामों अजय चंद्राकर एवं अमर अग्रवाल पर अपने शासनकाल में भ्रष्टाचार और कदाचार के कई गंभीर आरोप लगे हैं। उनका राजनीतिक जीवन कई विवादों और दागों से घिरा हुआ है। अमर अग्रवाल मंत्रीमंत्रित्व काल में प्रदेश का सबसे बड़ा ऑख फोड़वा कांड हुआ था। जिसको आज भी प्रदेश की जनता भूल नहीं पायी हैं। जबकि दूसरे दावेदार अजय चंद्राकर पर भ्रष्टाचार और चरित्रहीनता के कई आरोप हैं। ऐसी परिस्थिति में यदि इन दोनों में से किसी एक को भी मंत्रीमंडल में जगह दी जाती है तो साय सरकार की छवि को धूमिल होगी ही साथ ही बीजेपी पर भी कई सवाल खड़े होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को इन दोनों नामों को लेकर एक बार विचार जरूर

अजय चंद्राकर या अमर अग्रवाल, दोनों पर लगे हैं दाग!

करना होगा। जल्दबाजी यदि फैसला इनके ही पक्ष में गया तो निश्चित ही जिस उम्मीद और भरोसे के साथ प्रदेश की जनता ने पिछले पांच साल की भूपेश बघेल और उसकी चांडाल चौकड़ी के कुशासन के विरूद्ध बीजेपी को चुना है उनको काफी चोट पहुंचेगी। वैसे छत्तीसगढ़ भाजपा में इस बार लायक लोगों की कमी नहीं है पर अब मंत्रिमंडल के सदस्यों का चुनाव बहुत सोच समझकर करना चाहिए। क्योंकि यह सिर्फ पांच साल की बात नहीं है। बीजेपी की जड़े और मजबूत करने की बात है।

क्यों नहीं लेना चाहिए अजय चंद्राकर को मंत्रीमंडल में ?

पूर्व में अजय चंद्रकार पर भ्रष्टाचार और महिला शोषण से जुड़ी कई आरोप लग चुके हैं। ऐसे में उन्हें मंत्रीमंडल में शामिल करना भाजपा की बड़ी भूल हो सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार चंद्राकर की कार्यशैली कांग्रेस नेताओं से मिलती जुलती है। इसके साथ ही अजय चंद्राकर की छवि घमंडी एवं बदतमीज व्यक्ति की रही है। इसके इन पर आरोप लगे हैं जिसे मीडिया ने खूब छापा भी है। ऐसे में उन्हें मजबूत पोर्टफोलियों देना भी बड़ी भूल हो सकती है। ऐसे में अगर भाजपा चंद्राकर को मंत्रीमंडल में शामिल करती है तो एक बार फिर वह अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि मंत्रीमंडल के एक सदस्य की भी खराब छवि पूरी सरकार को बदनाम करती है। जिसकी सफाई पूरी सरकार को देना पड़ती है।

क्यों नहीं लेना चाहिए अमर अग्रवाल को मंत्रीमंडल में ?

रमन सिंह सरकार में अमर अग्रवाल ने अमानवीयता और भ्रष्टाचार के सारे कीर्तिमान तोड़ दिए थे। नगरीय प्रशासन, वाणिज्यिक कर, चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए अग्रवाल ने गुड़ाखू उत्पादक के रूप में अपने कारोबार को चहुं ओर फैलाते हुए लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी में कैंसर का जहर फैलाने में कोई

कोर-कसर नहीं छोड़ी। गुड़ाखू में अमानक और घातक रसायनों का उप्रयोग करके छत्तीसगढ़ ही नहीं, आसपास के राज्यों में भी कैंसर का जहर घोल रहे छत्तीसगढ़ के इस स्वास्थ्य मंत्री के लिए सिर्फ पैसा कमाना ही एकमात्र मकसद रहा था। स्वास्थ्य विभाग ही नहीं, वाणिज्यिकर, चिकित्सा शिक्षा और नगरीय प्रशासन मंत्री के रूप में भी घोटालों के अनेक काले इतिहास रचे हैं। अमर अग्रवाल ने पैसे को लालची डाक्टरों द्वारा सैकड़ों महिलाओं के गर्भाशय बगैर कारण निकाल देने के नारकीय हथकंडों को शह दी थी। सूत्रों का कहना है कि कालाधन अर्जित कर अमर अग्रवाल 2000 करोड़ रु पये से भी ज्यादा के आसामी बन चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री के रूप में एक के बाद एक घृणित अध्याय लिखते जा रहे अमर अग्रवाल को आंखफोड़वा मंत्री भी कहा जाने लगा था। स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए कुशासन और भ्रष्ट तथा निकम्मों को प्रश्रय देने वाले अमर अग्रवाल की धनलोलुपता के कारण प्रदेश का चिकित्सा तंत्र पूरी तरह अनुशासनहीन और अमानवीय रूख अपना रहा था। यदि ऐसे भ्रष्टाचारी को मंत्री बनाया जाता है तो सवाल उठना लाजिमी है।

मोदी कैबिनेट में बृजमोहन अग्रवाल को मिलनी चाहिए जगह

हाल ही हुए लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ से बृजमोहन अग्रवाल बंपर वोटों से चुनाव जीतकर आये हैं। प्रदेश की 11 सीटों में से बीजेपी ने 10 सीटों पर जीत हासिल की है। इन 10 सीटों के जीतने में साय सरकार में मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बड़ा योगदान है। क्योंकि अग्रवाल प्रदेश के बड़े नेता हैं। पिछली सभी सरकारों में वह सरकार का हिस्सा रहे हैं। लेकिन हाल ही में मोदी कैबिनेट में उनको जगह नहीं दी गई है। छत्तीसगढ़ कोटे से केवल एक सदस्य को मंत्री बनाया गया है। जबकि ज्यादा सीटों जीतने के कारण कम से कम दो सांसदों की जगह बनती है। वर्तमान में मोदी सरकार अपने मंत्रीमंडल में 81 मंत्री रख सकते हैं। फिलहाल 73 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है। अभी भी 08 सदस्यों की जगह खाली है। आने वाले समय में मोदी को बृजमोहन अग्रवाल के नाम पर जरूर विचार करना चाहिए। बृजमोहन अग्रवाल छत्तीसगढ़ में लगातार 8वीं बार विधानसभा का चुनाव जीते हैं और राज्य के कद्दावर नेताओं में शामिल हैं।

अमीरों को छूट गरीबों की लूट

रघु ठाकुर

मीडिया में, इस आशय की खबरें आई है कि देश की अर्थव्यवस्था इस वर्ष लगभग 8 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल करेगी। वैसे तो सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि 2030 तक देश की आर्थिक विकास की दर 25 प्रतिशत तक पहुँच जायेगी। परन्तु इस सरकार की अवधि अभी 2024 तक है और इसलिये उसके बाद की संभावनाओं के बारे में आंकलन औचित्यपूर्ण नही है। महत्वपूर्ण बात यह है की, जिसकी चर्चा जरुरी भी है कि देश में विकास की दर में वृद्धि 7 प्रतिशत से कुछ अधिक है, तथा आत्म हत्याओं की वृद्धि की दर भी कुल मौतों की लगभग 7 प्रतिशत है। आखिर इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है। पिछले एक वर्ष में लगभग 1 लाख से अधिक आत्महत्यायें इस देश में हुई हैं, जिनमें लगभग 6 हजार छात्र है, 25 हजार के करीब बेरोजगार है, किसान है और गरीब लोग है। तब यह क्या वजह है कि देश के इतने विकास के बावजूद भी छात्र बेरोजगार, किसान, गरीब आत्महत्यायें करने को लाचार है। इस तथ्य को इस खबर के साथ समझना होगा कि अडानी दुनिया के अमीरो की सूची मे तीसरे नं. के अमीर बन गये हैं। अम्बानी भी दुनिया के अमीर लोगो की सूची में है यद्यपि पिछले वर्ष की उनकी सम्पत्ति में कुछ कमी होने की वजह से वे अडानी से पिछड़ गये। देश के अन्य उद्योगपतियों ने भी पिछले वर्षो में भारी मुनाफा कमाया है।

दूसरी ओर गरीबों की औसत आय में

वृद्धि तो दूर कुछ कमी ही आई है। जब राज्यवार देश में प्रति व्यक्ति औसत आय का आँकड़ा निकाला जाता है तो उसमें देश की राजधानी दिल्ली एक लाख प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष औसत आय का आंकड़ा आता हैं जबकि उसी दिल्ली में कई लाख साईकिल रिक्शा चलाने वाले लोग है जो किसी ढाबे पर रोटी दाल खाकर तथा बैठकर कुछ समय के लिये चलने वाले टी.वी. को देखकर अपने दुःख भूल जाते है और बाद में कुछ पीकर या वगैर पीकर रात में अपने साईकिल रिक्शा पर ही बन्दर की भांति सो जाते है। ऐसी स्थिति अकेले इन रिक्शे वालों की नही है बल्कि दिल्ली के लगभग 30 से 40 लाख लोग इनमें सुरक्षा प्रहरी, माल बेचने वाले हाकर, हज्जाम हाथ से कपड़े धोने वाले धोबी, मोची व ऐसे ही अन्य शामिल हैं की आय से 15 हज़ार रूपया प्रतिमाह है। औसत आय का आँकड़ा एक बड़ा छल होता है। जहाँ एक तरफ एक उद्योगपति 20-30 करोड़ रु. रोज कमा लेता है वही दूसरी तरफ शहरी क्षेत्रों में गरीबी में जीने वाला मात्र 300 से 500 रुपये रोज तक कमा पाता है। परन्तु औसत आय के आँकड़े में 30 करोड रोड़ कमाने वाला और 300 रु. रोज कमाने वाला एक दूसरे के समान हो जाते है। औसत आंकड़े विषमता को छिपाने के सबसे बढिया माध्यम है।

आय का आँकड़ा एक बड़ा छल होता है। जहाँ एक तरफ एक उद्योगपति 20-30 करोड़ रु. रोज कमा लेता है वही दूसरी तरफ शहरी क्षेत्रों में गरीबी में जीने वाला मात्र 300 से 500 रुपये रोज तक कमा पाता है। परन्तु औसत आय के आँकड़े में 30 करोड रोड़ कमाने वाला और 300 रु. रोज कमाने वाला एक दूसरे के समान हो जाते है। औसत आंकड़े विषमता को छिपाने के सबसे बढिया माध्यम है।

फिर यह भी ध्यान में रखना होगा कि दिल्ली केन्द्र की राजधानी है जहाँ कई लाख केन्द्रीय सरकार के सेवानिवृत्त पेंशनधारी है, कई लाख वर्तमान में काम करने वाले सरकारी कर्मचारी है, लाखो

निजी क्षेत्र में बड़े-बड़े पैकेज पर काम करने वाले कर्मचारी है। इसलिये वहाँ का औसत आय का आंकडा अन्य राज्यों की तुलना में बड़ा नजर आता है। अगर इसका संबंध केन्द्र या राज्य के विकास के साथ होता है तो इसका उत्तर केन्द्र राज्य की सरकार से पूँछा जाना चाहिये कि आप अनाज या खाद्यान्न कई लाख लोगों को 5 किलो प्रति व्यक्ति मुफ्त में क्यों बांटते है? या दिल्ली की सरकार 300 यूनिट बिजली व पानी फ्री क्यों देती है? ये लोग खुद खरीद कर क्यों नही खा सकते? अपना घर क्यों नहीं जगमगा सकते तथा अपने आय के साधनों से नल का बिल चुकाकर पानी क्यों नहीं पी सकते?

दरअसल देश के, विकास में बनाये जाने वाले ढांचे में भी त्रुटियां हैं। देश में साधनों और सम्पत्ति का बंटवारा समान क्यों नही होता? अगर यह हो जाये तो सही अर्थो में सबका साथ सबका विकास कहा जा सकता है। परन्तु सबका विकास तब तक अर्थहीन नारा है जब तक कि वह सबका समान विकास के नारे में तब्दील नहीं होता।

भारत सरकार ने अभी कुछ दिनो पहले खाद्य सामग्री और यहाँ तक की आटे पर भी जी.एस.टी. लगा दिया है। यह समझना होगा कि गरीब जो श्रम करता है अतः उसके पेट की भूख ज्यादा होती है और अमीर को तो एक दो रोटियां पचाने के लिये दवा लेना पड़ती है। मान ले दिल्ली में कर्मचारी, पेंशनधारी आदि सब मिलाकर 15-20 लाख लोग ऐसे है जो उच्च मध्यम वर्ग में आते हैं। वे एक माह में 2 करोड़ कि.ग्रा. आटा या अनाज खाते हैं। जिसका बाजार मूल्य लगभग 60 करोड़ रूपया के आसपास होता हो और दिल्ली का यह अमीर तबका 5 प्रतिशत जी.एस.टी. देगा। और अगर थोड़ी देर के लिये यह भी मान ले गरीब व श्रमिक की की भूख ज्यादा न हो तथा उतना ही अनाज दिल्ली के गरीब अति गरीब मध्यम वर्ग के लोग खाते हो तो एक माह में 1 हज़ार करोड़ किलो खाद्य यानि न्यूनतम 30 हजार करोड़ की कीमत का खाद्य खायेंगें और उस पर भी 5 प्रतिशत जी.एस.टी. देने का मतलब है कि गरीबों से 1500 करोड़ रूपये की जी.एस.टी. की आय भारत सरकार को होगी जिसका एक हिस्सा राज्य को भी जायेगा। यह कटु सत्य है कि देश का गरीब खाद्यान्न ज्यादा टैक्स देगा । तथा अमीर जो ज्यादा आय कमाता है वह कम टैक्स देगा इतना ही नही यहाँ एक तरफ भारत सरकार ने आटे पर

जी.एस.टी. लगाई वहीं दूसरी तरफ उसी समय कारपोरेट की जी.एस.टी. में 5 प्रतिशत की कमी कर दी गई। यानि अमीर को छूट गरीब की लूट। यह है देश की सरकारों का असल चेहरा और यही कारण है कि देश के छात्र, बेरोजगार, गरीब और छोटे किसान आत्महत्यायें करते है। भारत सरकार के प्रचारकर्ता यह भी बहुत प्रचार करते हैं कि देश का विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ा है। परंतु यह तथ्य छिपा लेते हैं कि देश पर विदेशी कर्ज कितना बढ़ा है। वर्ष 2021-22 में भारत का विदेश व्यापार का घाटा यानि हमारा इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच का अन्तर लगभग 2 लाख करोड़ रूपये का रहा है। एक्सपोर्ट (निर्यात) कम है इंपोर्ट (आयात) ज्यादा है। आज भारत पर लगभग 6.5 लाख करोड़ रूपये का विदेशी कर्ज है। यही मेड इन इंडिया जैसे नारों की भी असलियत है।

मैं जानता हूँ कि कोई भी सरकार हो, सभी बेरोजगारो को सरकारी नौकरियां नहीं दे सकती। परन्तु कम से कम इतना तो सरकार कर सकती है कि जब तक हर बेरोजगार को नौकरी या कोर्ट अन्य काम न मिल जायें तब तक उन्हें बेरोजगारी भत्ता दे। अगर सरकार, सांसदों, विधायकों को पेशन दे सकती है, कर्मचारियों को बुढ़ापे के सहारे के लिये फण्ड या ग्रेज्युटी की एकमुश्त राशि दे सकती तो क्या बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं दे सकती।

आये दिन भारत सरकार के समर्थक लोग अमेरिका और यूरोप से देश की तुलना करते हैं। कभी-कभी ऐसे भी समाचार छपते हैं या छपवाये जाते हैं कि देश ने इतनी तरक्की की है कि वह यूरोप से आगे निकल गया है और कुछ सालों में अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। परन्तु अमेरिका या यूरोप के अन्य कई देशों मे सरकार बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ताा देती है।

अगर देश के कारपोरेट कर में सरकार 5 प्रतिशत की कमी कर उन्हें कई लाख करोड़ का फायदा पहुँचा सकती है उन पर 3 प्रतिशत जी.एस.टी. टैक्स बढ़ाकर सरकार को आसानी से 1 लाख करोड़ रू. मिल सकता है तो और मात्र इतने से ही बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था हो सकती है। तथा बेरोजगारी भत्ता दिया जा सकता है। पढ़ा हो या गैर पढ़ा हो सभी बेरोजगारों को 5 हज़ार रूपये प्रति महीने का भत्ता दिया जा सकता हैं। सवाल पैसे का नहीं है सवाल है नीतियों का, मन के संकल्प का।

गठबंधन बनाम क्षेत्रीय दलों की राजनीति में उभार

भाजपा स्पष्ट बहुमत से 32 सीटें पीछें रह गई। हालांकि उसके नेतृत्व वाले राजग गठबंधन के पास 291 सीटें हैं। अतएव राजग बहुमत में है। लेकिन भाजपा खुद 272 सीटें लाई होती तो उसकी पूर्व की तरह ठसक बनी रहेती। बावजूद नरेंद्र मोदी नेहरू के बाद ऐसे अकेले प्रधानमंत्री हैं, जिन्हें मतदाता ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने रहने का जनादेश दिया है।

प्रमोद भार्गव

जिस तरह से शक्ति और सत्ता राजनीति के आधारभूत सिद्धांत माने जाते हैं, उसी तरह राजनीति से यह मान्यता भी जुड़ी है कि राजनीति में वही आगे बढ़ते हैं, जो अवसर का लाभ उठाकर उसे भुनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी के लिए गठबंधन की राजनीति के बीते दस साल में लगभग यही पर्याय रहे हैं। बीते सालों में महाराष्ट्र और हरियाणा में भाजपा, शिवसेना, अकाली दल और इनेलो से दशकों से चले आ रहे गठबंधनों का टूटना इन्हीं आशयों के परिणाम थे। लेकिन अब आए चुनाव परिणामों ने अकेली भाजपा को 240 सीटों पर सिमटा दिया। भाजपा स्पष्ट बहुमत से 32 सीटें पीछें रह गई। हालांकि उसके नेतृत्व वाले राजग गठबंधन के पास 291 सीटें हैं। अतएव राजग बहुमत में है। लेकिन भाजपा खुद 272 सीटें लाई होती तो उसकी पूर्व की तरह ठसक बनी रहेती। बावजूद नरेंद्र मोदी नेहरू के बाद ऐसे अकेले प्रधानमंत्री हैं, जिन्हें मतदाता ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने रहने का जनादेश दिया है। यह करिश्मा 62 साल बाद

हुआ है। लेकिन अब पेंडुलम की तरह लटकी भाजपा को 16 सीटें जीतने वाले चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी और 16 सीटें जीतने वाली नीतीश कुमार की जदयू से पूरे पांच साल बैसाखियों का सहारा लेना पड़ेगा। ये दोनों दल किंगमेकर की भूमिका में आ गए है। इन और अन्य सहयोगी दलों के साथ भाजपा तीसरी बार केंद्र में सत्तारूढ़ होने जा रही है।

शक्ति अर्थ की हो या राजनीतिक सत्ता की जब वह उम्मीद से ज्यादा हाथ लग जाती है तो महत्वाकांक्षाएं बेलगाम होने लगती हैं। लिहाजा 2014 और 2019 की अप्रत्याशित जीत के बाद भाजपा की जहां महत्वाकांक्षा बढ़ी, वहीं आत्मविश्वास प्रबल हुआ। नतीजन नरेंद्र, अमित की युगल जोड़ी ने भाजपा को गठबंधन से मुक्ति के पंखों पर सवार कर दिया था। भाजपा चाहने लगी थी कि यदि राजनीतिक पहुंच वाले राज्य में उसकी अकेले दल के रूप में पकड़ मजबूत होगी तो वह कालांतर में गठबंधन की लाचारी से मुक्त होती चली जाएगी। इसी धारणा के चलते उसने अपने सबसे पुराने सहयोगी शिवसेना और अकाली दल से नाता तोड़ लिया था। दरअसल भाजपा की जो राजनीति, संस्कृति और कार्यशैली है, कमोवेश वही शिवसेना की है। दोनों उग्र हिंदुत्व और राष्ट्रीय सांस्कृतिक एकात्मवाद के अनुयायी हैं। लेकिन भाजपा गठबंधन में सहयोगी रहे जिस राज्य में भाजपा को सबसे बड़ा झटका लगा हैए उसमें महाराष्ट्र प्रमुख है। 2014 और 2019 में महाराष्ट्र की 48 सीटों में से भाजपा, शिवसेना को 41 सीटें मिली थीं। 2019 के विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत के बावजूद मुख्यमंत्री पद को लेकर दोनों दलों में बिगड़ गई। इसी के साथ राज्य की राजनीति में बदलाव आ गया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस, एनसीपी के साथ मिकर सरकार बनाई तो भाजपा ने शिवसेना में विभाजन कर सरकार गिरा दी और एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनवा दिया। यही नहीं एकनाथ शिंदे की ही शिवसेना को असली होने का दर्जा मिल गया। साथ ही शरद पवार की एनसीपी के भी दो टुकड़े कर दिए। भतीजे अजीत पवार ने चाचा की पार्टी छीन ली। हालांकि यह कदम उल्टा पड़ा। उद्धव और शरद पवार ने मराठी अस्मिता को मुद्दा बनाया और मतदाता की सहानुभूति बटोरने में

सफल रहे। अब यहां सबसे ज्यादा 13 सीटें जीतकर कांग्रेस बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। शिवसेना उद्धव को 9, एनसीपी शरद को 7 सीटें मिली हैं। भाजपा को दस सीटों पर संतोष करना पड़ा है। चूंकि इस चुनाव में अजीत पवार को मात्र एक सीट मिली है। इससे उनकी नेतृत्व क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। महाराष्ट्र में इसी साल अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव के इन नतीजों का असर विधानसभा चुनाव पर भी दिखाई दे सकता है। अतएव महाराष्ट्र में अब कांग्रेस, एनसीपी शरद और शिवसेना उद्धव के एक साथ आने से महाविकास अघाड़ी की ताकत बढ़ गई है, जो भाजपा को महंगी पड़ सकती है।

आंध्र प्रदेश में भाजपा के सहयोगी तेलगु देशम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने 16 सीटों पर जीत हासिल की है। आंध्र प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में भी नायडू को सरकार बनाने के लिए स्पष्टर बहुमत मिल गया है। नायडू ने कह भी दिया है कि आंध्रप्रदेश की जनता ने राजग के साथ हमारे गठबंधन पर भरोसा करके हमें बड़ी जीत दिलाई है। हम राजग के साथ है। साफ हैए नायडू केंद्र सरकार में अपने सांसदों को मंत्री बनाकर भाजपा को ताकत देते रहेंगे। इधर बिहार में राजग गठबंधन ने बड़ी संख्या में सीटें हासिल करके लालू और तेजस्वी यादव को आईना दिखा दिया है। यहां चालीस सीटों में से 12 जदयू, 12 भाजपा, और पांच लोजपा ने जीती हैं। अतएव कहा जा सकता है कि चुनाव से पहले नीतीश कुमार के जदयू को साथ लाकर बड़े नुकसान से बच गई। बिहार के इन परिणामों से गठबंधन की महिमा को स्थापित किया है। जदयू नेता केसी त्यागी का कहना है कि चुनाव पूर्व राजग से गठबंधन को लेकर हमारी जो प्रतिबद्धताएं हैंए वे बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश और नायडू को अच्छी जीत के लिए बधाई दे दी है।

दस साल बाद इस चुनाव में एक बार फि र क्षेत्रीय मुद्दों और क्षेत्रीय दलों का प्रभाव दिखाई दिया है। क्षेत्रीय दलों की

राजनीतिक ताकत स्थानीय मुद्दे और जातीयता होती है। देश के सबसे ज्यादा संसदीय 80 सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश में मायावती, मुलायम सिंह और अखिलेश यादव को जब भी सत्ता का सुख मिला है, उसमें यही राजनीति के गुण शामिल रहे हैं। यही सब दक्षिण भारत के राज्यों में क्षेत्रीय क्षत्रपों का दबदबा देखने में आया। तमिलनाडु में स्टालिन की द्रमुक ने इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर राज्य की सभी 39 सीटों पर जीत दर्ज करा ली है। आप के साथ मिलकर कांग्रेस ने पंजाब में सभी 10 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में डलवा दी। पश्चिम बंगाल की क्षेत्रीय नेता ममता बनर्जी ने अपने जादू को बनाए रखा है। तृणमूल ने महिला और मुस्लिम मतदाताओं को साधकर 30 सीटों पर सफलता प्राप्त की। जबकि उसकी 2019 में 22 सीटें थीं। भाजपा को यहां 2019 में जीतीं 18 सीटों की तुलना में 2024 में 11 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा है। ममता ने बंगाल में इंडिया के साथ कोई गठबंधन भी नहीं किया था। वे अकेली चलीं और उन्होंने भाजपा के सीएए एवं संदेशखाली के मुद्दों को नाकाम कर दिया। तय है, ममता आगे भी क्षेत्रीय क्षत्रप बनी रहेंगी। वे अब सीएए और एनआरसी का भी संसद में अपने सांसदों से मुखर विरोध कराएंगी। भाजपा के चर्चित चेहरे सुरेश गोपी ने केरल में जीत दर्ज कराकर एक बड़ी कामयाबी दर्ज की है।

भाजपा स्पष्ट बहुमत में जरूर नहीं है लेकिन उसने अपनी पार्टी का विस्तार करते हुए ओडिशा में जबरदस्त दस्तक दी है। नवीन पटनायक के 24 साल से चले आ रहे राज को खत्म करके भाजपा ने जता दिया है कि वे पार्टी के देशव्यापी विस्तार के लिए संघर्ष करती रहेंगी। ओडिशा में भाजपा को दोहरी खुशी मिली है। यहां उसने लोकसभा की 21 सीटों में से 19 सीटें जीतकर अप्रत्याशित ढंग से अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा दी है। दूसरी तरफ भाजपा को यहां हुए विधानसभा चुनाव में भी स्पष्ट बहुमत मिल गया है। विधानसभा की कुल 147 सीटों में से भाजपा ने 78 सीटों पर विजय हासिल की है। नवीन पटनायक के बीजू जनता दल को 51 सीटों पर संतोश करना पड़ा है। भाजपा की इस बड़ी जीत में यहां की मूल निवासी द्रोपदी मुर्मु को राश्ट्रपति बनाया जाना भी रहा है। नवीन पटनायक उम्रदराज होते जा रहे हैं और उन्होंने अपने दल के किसी नेता को अपने समकक्ष नहीं बनाने की बड़ी भूल की है। अतएव आगे यह पार्टी कितना चल पाएगीए कहना मुश्किल है।

क्षेत्रीय क्षत्रपों में सबसे बड़ी ताकत के रू प में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी आई है। उसने 80 सीटों में से 37 सीटें जीतकर अपनी मजबूत आमद लोकसभा में दर्ज करा दी है। यहां से अब बसपा के सूपड़ा साफ होने का लाभ भी सपा को मिला है। राम मंदिर निर्माण के बावजूद भाजपा के लिए यहां से मिलीं अप्रत्याशित पराजय ने यह तय कर दिया है कि भारत में क्षेत्रीयता और जातीयता अभी भी चुनाव में ईश्वर से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि भाजपा ने यहां से 33 और उसके सहयोगी दलों ने छह सीटें जीती हैं। भाजपा को यहां नुकसान मुस्लिम बहुल प्रदेश होने के कारण भी उठाना पड़ा है। जबकि समाजवादी पार्टी ने गिनती के चार मुस्लिम मैदान में उतारे थे, जिनमें से तीन ने जीत हासिल की है। सपा की इतनी बड़ी जीत का कारण मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट नहीं देना भी रहा है। क्योंकि यदि मुस्लिमों को टिकट दिए होते तो उनका जीतना हिंदू वोटों के धुरवीकरण के चलते मुश्किल था। बहरहाल क्षेत्रीय क्षत्रपों ने रणनीतिक रूप से एक होकर जता दिया है कि क्षेत्रीयता और जातियता की राजनीति से भारत अभी मुक्तनहीं होने जा रहा है। राहुल गांधी इसे संविधान बदलने और अनुसूचित जातियों व जनजातियों को आरक्षण से बाहर करने की धार देकर भाजपा नेतृत्व वाले राजग गठबंधन की इकतरफा जीत में दीवार बनकर खड़े हो गए। गोया, अब भाजपा एक देश एक चुनाव, जनसंख्या नियंत्रण और समान नागरिक संहिता जैसे कानून नहीं बना पाई।

कैसे खत्म होगी बाल मजदूरी

डॉ. गीता गुप्ता

आज भी बाल-श्रम भारत की एक गंभीर समस्या है। यद्यपि हाल के वर्षो में सरकार का ध्यान बच्चों की समस्याओं पर केन्द्रित हुआ है। इसीलिए अब अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून का रूप ले चुका है और बाल यौन शोषण पर विराम लगाने हेतु भी कानून अस्तित्व में आ गया है। परन्तु बाल श्रम रोकने में सरकार सफल नहीं हो पाई हैं। यह चिंताजनक है। समूची दुनिया में बाल श्रमिकों की संख्या 24 करोड़ से भी अधिक है। इनमें से एक तिहाई से भी अधिक बच्चे खदानों, खतरनाक मशीनों, खेतों, घरेलू कार्यो और दूसरे प्रतिबंधित कार्यों में लगे हुए है।इस तरह बुनियादी सुविधाओं से वंचित बच्चों की संख्या निरंतर बढ़ रही है।

समूची दुनिया में बाल श्रमिकों की संख्या 24 करोड़ से भी अधिक है। इनमें से एक तिहाई से भी अधिक बच्चे खदानों, खतरनाक मशीनों, खेतों, घरेलू कार्यो और दूसरे प्रतिबंधित कार्यों में लगे हुए है।इस तरह बुनियादी सुविधाओं से वंचित बच्चों की संख्या निरंतर बढ़ रही है।

बच्चों की खराब स्थिति के मद्देनजर विश्व में भारत छठे स्थान पर है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, यहां लगभग बारह करोड़ बाल मजदूर है और ये सभी 14 वर्ष से कम उम्र के हैं। हालांकि संसद में सरकार के कथनानुसार 15 वर्ष से कम आयु के सवा करोड़ से कुछ अधिक बच्चे

स्कूल जाने की बजाय पेट की भूख मिटाने के लिए कठोर श्रम करने की विवश हैं। देश के विभिन्न राज्यों में स्थितियां अलग-अलग है परन्तु शोषित, उत्पीड़ित घर से भागे हुए, यौन उत्पीड़न के शिकार और निषिद्व क्षेत्रों में मजदूरी कर रहे बच्चे तो हर राज्य में है और इनकी संख्या में लगातार बढ़ोत्तरी इसलिए हो रही है क्योंकि समाज में कानून का कोई डर नहीं है।

भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 16 खतरनाक व्यवसायों एवं 65 खतरनाक प्रक्रियाओं की बाकायदा सूची जारी कर उनमें 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को रोजगार देना निषिद्व घोषित किया है। फिर भी हर शहर, हर गली-मुहल्ले में बच्चे प्रतिबंधित कार्यो में लगे हुए देखे जा सकते हैं।चाय के ठेलों, ढाबों, मोटर-गैरेज और घरों में कामगार के रूप में बच्चे ही पहली पसंद होते हैं, क्योंकि कम मेहनताने पर अधिक काम लिया जा सकता है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाने वाला मीडिया भी बच्चों का शोषक है। हर शहर, रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड और सड़को पर अखबार बेचते बच्चे बाल श्रम का ही प्रमाण हैं। मगर कोई पत्रकार, ग्राहक या अखबार मालिक इस बाल श्रम के विरूद्व आवाज नहीं उठाता। कैसी विडंबना है।

सरकार ने स्कूल चले अभियान चलाया है, मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था की है, शिक्षा को बच्चों का अधिकार घोषित किया है। लेकिन बच्चों का बचपन सुरक्षित नहीं हो पा रहा है। वे शोषित और कुपोषित ही हैं। कोई शासकीय योजना उनके उज्जवल भविष्य की गारंटी नहीं बन पा रही है तो दोष किसका है? राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर महिला बाल विकास विभाग तथा बाल अधिकार संरक्षण आयोग के होते हुए भी बच्चे अपने अधिकारों से वंचित हैं। उन्हें श्रम से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, आखिर क्यों? बाल मजदूरों के पुनर्वास हेतु सरकार ने कार्यक्रम बनाये हैं। राष्ट्रीय बाल श्रम

भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 16 खतरनाक व्यवसायों एवं 65 खतरनाक प्रक्रियाओं की बाकायदा सूची जारी कर उनमें 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को रोजगार देना निषिद्व घोषित किया है। फिर भी हर शहर, हर गली-मुहल्ले में बच्चे प्रतिबंधित कार्यो में लगे हुए देखे जा सकते हैं।चाय के ठेलों, ढाबों, मोटर-गैरेज और घरों में कामगार के रूप में बच्चे ही पहली पसंद होते हैं, क्योंकि कम मेहनताने पर अधिक काम लिया जा सकता है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाने वाला मीडिया भी बच्चों का शोषक है। हर शहर, रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड और सड़को पर अखबार बेचते बच्चे बाल श्रम का ही प्रमाण हैं। मगर कोई पत्रकार, ग्राहक या अखबार मालिक इस बाल श्रम के विरूद्व आवाज नहीं उठाता। कैसी विडंबना है।

परियोजना के तहत बाल श्रमिकों के लिए विशेष स्कूल पुनर्वास केन्द्र औपचारिक/अनौपचारिक शिक्षा, मध्यान्ह भोजन, छात्रवृत्ति, व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वास्थ्य-सुविधाओं का प्रावधान किया गया है। बाल श्रम रोकने के लिए कानून भी बनाये गए हैं। बाल मजदूर (प्रतिबंधित एवं विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत दोषी व्यक्ति को दस हजार से बीस हजार रूपये के अर्थदंड सहित एक वर्ष की सजा का भी प्रावधान है। लेकिन यह तयशुदा बात है कि कोई कानून तभी कारगर हो सकता है जब उसका पालन सुनिश्चित किया जाए।

जिन खतरनाक व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में बाल मजदूरी निषिद्ध है, उन पर सरकार को निगरानी रखनी चाहिए! हमारे आस पास ही बाल-श्रम के अनेक उदाहरण दिखाई देते है परंतु किसी नियोक्ता की कभी कोई शिकायत नहीं करता, न ही उसे दंडित किया जाता है तो बाल श्रम कैसे रूकेगा? देखा गया है कि निर्धन माता-पिता भी स्वयं बच्चों को मजदूरी के लिए भेजते हैं। वे उनकी शिक्षा में रूचि नहीं लेते क्योंकि पेट पालने में बच्चे उनके सहायक होते हैं। ऐसे में बच्चे कभी-कभी बंधुआ मजदूर बनकर रह जाते हैं। ऐसे परिवारों के आर्थिक स्वावलंबन का उपाय भी सरकार को करना होगा। बाल श्रमिकों की समस्या यदि सचमुच हल करनी है तो बाल श्रमिक अधिनियम को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करना होगा और बाल श्रमिक विरोधी कानून तथा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना को शिक्षा के अधिकार कानून के अनुरूप बनाना होगा। ताकि बेसहारा, बेघर बच्चों और बाल श्रमिकों को पुनर्वास के माध्यम से शिक्षा के अधिकार का सीधा लाभ मिल सके, क्योंकि शिक्षा से ही बच्चों का जीवन प्रकाशमय हो सकेगा।

मेरा मानना है कि जनता के सहयोग के बिना कोई भी कानून बाल श्रम के कलंक से इस देश को मुक्ति नहीं दिला सकता। बच्चों के हित में जितने भी कानून बने है, उनका लाभ जब तक बच्चों को नहीं मिलेगा वे देश की उन्नति में भागीदार नहीं बन सकेंगे और जब तक बच्चों का बचपन नहीं संवरेगा तब तक देश के उज्जवल भविष्य की कल्पना निरर्थक है, क्योंकि बच्चों पर ही देश का भविष्य अवलंबित है। ऐसे में, राष्ट्र के हर नागरिक का कर्तव्य है कि अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझे और बच्चों को जहां भी मजदूरी करते देखे, उन्हें शिक्षा की रोशनी में ले जाने और उनके अधिकार दिलवाने का प्रयास करें तभी सरकार की बाल श्रम परियोजना स्कीम सफल होगी और हमारा देश बाल मजदूरी के कलंक से छुटकारा पा सकेगा।

बारूद के ढेर पर पाकिस्तान!

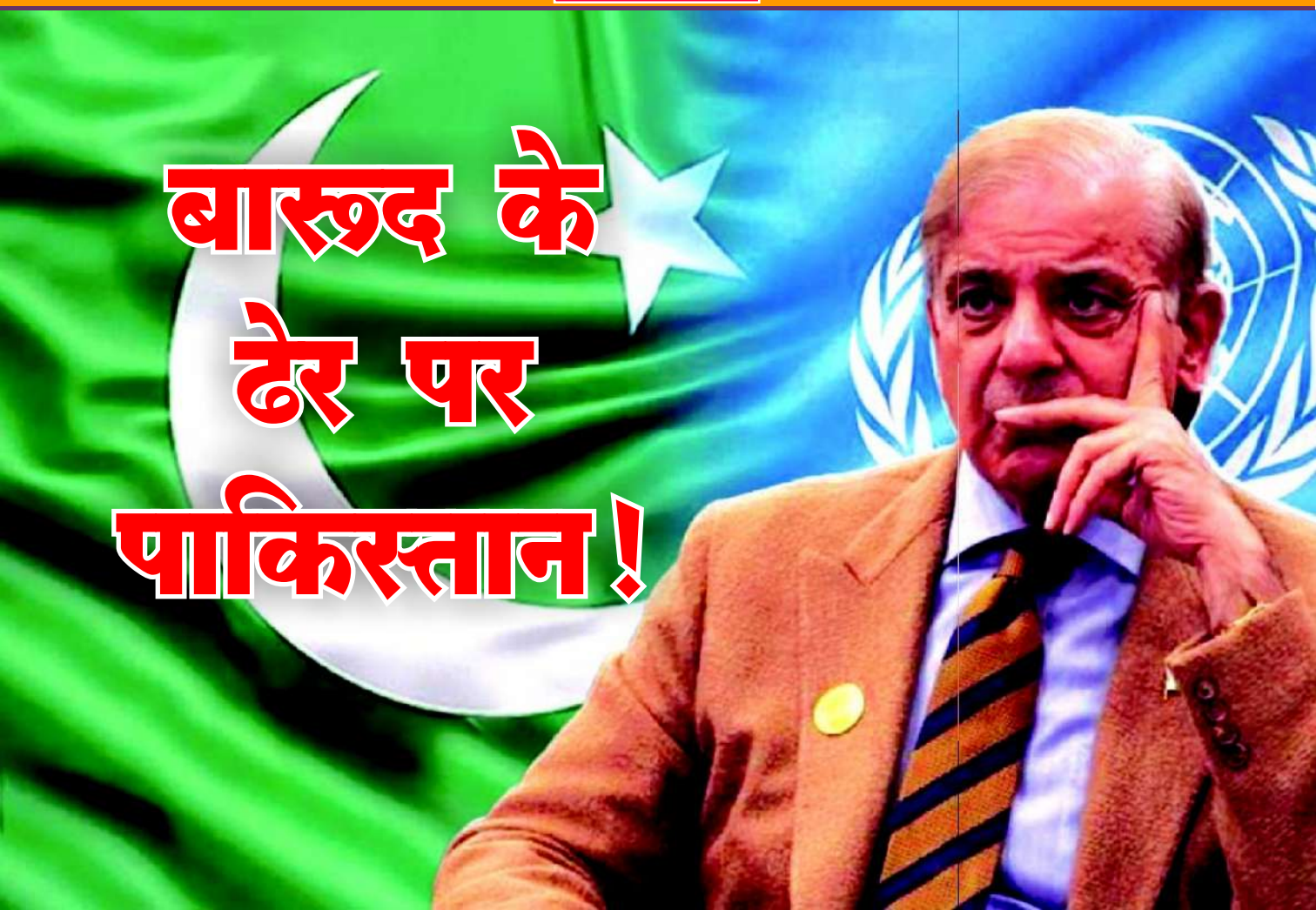

पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पतन की ओर अग्रसर है और एक अर्थ में डूबती अर्थव्यवस्था कही जा सकती है। पिछले दशकों में पाकिस्तान ने दुनिया से, विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से भारी कर्ज लिया है, उस कर्ज को चुकाना संभव नहीं हो रहा है। हाल ही में ऐसी खबरें आई हैं कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की टीम पाकिस्तान को इस कर्ज के भुगतान की स्थिति से बचाने के लिये और एक नया कर्ज जो उसे बेल आउट करने के लिये है, उसे किन शर्तों पर दिया जाय, इसकी चर्चा करने पाकिस्तान पहुंची है।

रघु ठाकुर

पिछले कुछ समय से पाकिस्तान देश और दुनिया की खबरों में प्रमुखता से छाया हुआ है। इसके अनेक कारण हैं, जिनकी चर्चा मैं आगे करूंगा। जो खबरें प्रमुखता से आ रही हैं वह यह है कि, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पतन की ओर अग्रसर है और एक अर्थ में डूबती अर्थव्यवस्था कही जा सकती है। पिछले दशकों में पाकिस्तान ने दुनिया से, विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से भारी कर्ज लिया है, उस कर्ज को चुकाना संभव नहीं हो रहा है। हाल ही में ऐसी खबरें आईं हैं कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की टीम पाकिस्तान को इस कर्ज के भुगतान की स्थिति से बचाने के लिये और एक नया कर्ज जो उसे बेल आउट करने के लिये है, उसे किन शर्तों पर दिया जाय, इसकी चर्चा करने पाकिस्तान पहुंची है।

अफगानिस्तान के जिन तालिबानियों को पाकिस्तान ने अपने यहां रखा था वे और उनका कट्टर पंथ पाकिस्तान के लिये खतरा बन गया है। उन तालिबानियों को पाकिस्तान अपने देश से निकाल कर अफगानिस्तान भेजना चाहता है। क्योंकि वे अनियंत्रित हो चुके हैं और पाकिस्तान की स्थितरता को खतरा बन चुके हैं। दूसरी ओर अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत उन्हें

संरक्षण दे रही है और कुछ अर्थों में पीठ सहला रही है। अफगान और पाक सीमा के दोनों ओर भारी तनाव है और हालात एक छोटे-मोटे मुठभेड़ के रूप में उभर रहे हैं।

पाकिस्तान के तीन हिस्सों में भयावह बैचेनी है। और वहां का जनमत पाकिस्तान और सेना के दबाव से मुक्ति चाहता है। बलूचिस्तान जहां के खान अब्दुल गफ्फार खान थे। वह गांधी के अनुयायी और भारत

विभाजन के खिलाफ थे। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो आजादी के पहले महात्मा गांधी की मांग पर बुलाई गई थी उस बैठक में महात्मा गांधी के भारत विभाजन के विरोध के प्रस्ताव का समर्थन करने वाले जो मात्र तीन लोग थे उनमें से एक सीमांत गांधी थे। उन्हें अपने भारत विभाजन के विरोध की भारी कीमत भी चुकानी पड़ी तथा पाकिस्तान बनने के बाद उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय पाक हुकूमत की जेलों में काटा या नजरबंद रहे। पख्तून लोगों ने कभी भी पाकिस्तान को इस रूप में स्वीकार नहीं किया और वे एकधर्म का देश बनाने के पक्षधर भी नहीं थे। किंतु मुस्लिम लोग और उसके मुखिया जिन्ना जो ब्रिटिश हुकूमत के हाथों खेल रहे थे और अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते भारत को बांटने के आपराधिक खेल में लगे थे। उन्होंने अंग्रेजों के साथ सांठ-गांठ कर पख्तूनों की आवाज को दबा दिया। कांग्रेस का उस समय का शीर्ष नेतृत्व केवल महात्मा गांधी को छोड़कर जो कांग्रेस के संगठनात्मक नेता भी नहीं थे वह न सदस्य और न पदाधिकारी थे, वह केवल नैतिक नेता थे। गांधी को कांग्रेस संगठन के नेतृत्व ने धोखा दिया। बापू की उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में घोर अवमानना की गई, जिसका शब्दसः वर्णन डॉ. राममनोहर लोहिया ने अपनी पुस्तक भारत विभाजन के अपराधी में किया है। नेहरू और पटेल जैसे गांधी के शिष्यों ने न केवल धोखा दिया बल्कि उन्हें अपमानित भी किया। गांधी के भारत विभाजन के विरोध को नकार दिया और उनके इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को भी महत्व नहीं दिया कि अगर भारत का विभाजन करना ही है तो वह अंग्रेज न करे। वे भारत छोड़कर चले जायें, बाद में हम भारतवासी आपस में मिलकर तय कर लेंगे। किंतु इसको भी कांग्रेस नेतृत्व ने स्वीकार नहीं किया। इस प्रस्ताव के बारे में डॉ. लोहिया ने लिखा कि मैंने अपने जीवन में कूटनीतिक प्रस्ताव कोई और नहीं देखा है। अगर इतना भी कांगे्रस नेतृत्व ने स्वीकार कर लिया होता तो भारत का विभाजन भी टल सकता था। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तथ्य के बाद भी कुछ लोग एक योजना के तहत महात्मा गांधी को भारत विभाजन का अपराधी मानते हैं। सीमांत

गांधी इस बंटवारे से इतने क्षुब्ध हुये थे कि उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व को सार्वजनिक रूप से इंगित कर कहा था कि आपने मुझे भेड़ियों के सहारे छोड़ दिया, वे सिंध और पंजाब के मुस्लिम नेताओं की कट्टरता और सत्ता की हवस को समझते थे, जो उस समय मुस्लिम लीग के और जिन्ना की टोली के सबसे बड़े भार बन चुके थे।

जिन्ना की मुस्लिम लीग भी देश के पश्चिम और पूर्व से ज्यादा समर्थन प्राप्त कर रही थी जहां कट्टरता और कट्टर तत्व मुस्लिम लीग के नेतृत्व में हिंसक रास्ते पर थे। जहां एक तरफ कांग्रेस नेतृत्व ने महात्मा गांधी की बात नहीं मानी, वहीं दूसरी ओर मुस्लिम लीग ने (डायरेक्ट एक्शन) यानी सीधी मारकाट कर बंटवारे की आग में घी झोंक दिया था। जो थोड़े बहुत विभाजन के खिलाफ मुस्लिम भाई थे, उनकी आवाज नक्कारखाने में तूती की आवाज बन गई थी। 1943 में भारत के एक पक्षधर अल्लाह बक्स की भारत के विभाजन के पक्षधरों और कट्टरपंथियों के द्वारा हत्या के बाद मुस्लिम लीग की उग्रता आसमान पर थी। ब्रिटिश हुकूमत का उनको संरक्षण था। वह कितना अधिक था इसका प्रमाण इससे मिलता है कि महात्मा गांधी के अनुयायी और भारत विभाजन के विरोधी अल्लाह बक्स की हत्या के मुकदमे में अभियोजन याने सरकार ने ठीक पैरवी तक नहीं की, जिससे हत्यारे रिहा हुये। यहां तक कि फैसला देने वाले जज ने दुखी होकर लिखा कि मैं अपराधियों को निर्दोष नहीं मानता हूँ

परंतु प्रमाणों के अभाव में उन्हें छोड़ना मेरी लाचारी है।

बलूचिस्तान भी कभी बंटवारे के पक्ष में नहीं था। और बलूचिस्तान के लोगों का पंजाब और सिंध के कट्टरपंथ तथा मुस्लिम लीग के साथ मतभेद थे। पाकिस्तान बनने के बाद पंजाब और सिंध के कट्टरपंथी सत्ताधीशों ने कभी भी बलूचिस्तान नागरिकों को बराबरी का दर्जा नहीं दिया और न न्याय संगत भागीदारी दी। आज स्थिति यह है कि बलूचिस्तान का जनमत उसी प्रकार पाकिस्तान से अलग होना चाहता है जिस तरह से पख्तूनिस्तान का।

पाक अधिकृत कश्मीर भी अब न केवल मानसिक बल्कि भौतिक रू प से विद्रोह की कगार पर है। वैसे भी यह अंचल भारतीय भूभाग था। जिसे हिंदुस्तान की संसद ने भी सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर भारतीय भूभाग माना है। यह तथ्य किसी से छिपा हुआ नहीं है कि जब कश्मीर के राजा ने पाकिस्तानी सेना के कबीलाई के

पाक अधिकृत कश्मीर भी अब न केवल मानसिक बल्कि भौतिक रूप से विद्रोह की कगार पर है। वैसे भी यह अंचल भारतीय भूभाग था। जिसे हिंदुस्तान की संसद ने भी सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर भारतीय भूभाग माना है।

रूप में हमले के बाद भारत में विलय का निश्चय किया। तब यह पीओके का हिस्सा कश्मीर का अभिन्न अंग था और स्वाभाविक है कि कश्मीर के विलय के बाद यह भारत का हिस्सा था। जिसे पाकिस्तान की सेना ने एक प्रकार से बलपूर्वक ले लिया था। उस समय भी कांग्रेस सरकार के नेतृत्वकर्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी सेना को आक्रमण करने से रु कवा दिया था बल्कि स्वतः संयुक्त राष्ट्र संघ जाकर युद्ध विराम के प्रस्ताव को रखना, वह उनकी भारी भूल थी। तभी से पाकिस्तान की सरकारें पीओके के नागरिकों के साथ दोहरा व्यवहार कर रही हैं। वहां निर्वाचन के नाम पर बलात पाकिस्तान की सैन्य हुकूमत पर दलालों को बंदूक की दया पर निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। अपने इस भेदभावपूर्ण जीवन से पीओके के नागरिक इतने दुखी हो चुके हैं कि वे पिछले कई सप्ताहों से सड़कों पर हैं और पाक से अलग होने के मानस में जी रहे हैं।

काश अगर आज गांधी जिंदा होते तो उनके प्रति समूचे भारतीय भूभाग के विश्वास और श्रद्धा की छत्रछाया में भारत विभाजन की नकली रेखा मिट जाती। काश अगर आज लोहिया जिंदा होते तो वे इस समूचे विद्रोह की आग में जल रहे अंचलों को साथ लेकर पाकिस्तान का राजनैतिक स्वरू प बदल देते। लोहिया की संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का जो जीवंत रूप 1960

के दशक में था, अगर आज होता तो इस समय विभाजन की रेखा को मिटाने के लिये एक महत्वपूर्ण भूमिका पार्टी निभा सकती थी। इस समय पूरे देश को एकजुट होकर पीओके को आजाद कराने और वापिस लेने की भूमिका में होना चाहिए। पर यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस के एक पूर्व नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान के परमाणु हथियार की चर्चा कर पीओके को आजाद होने से और पाकिस्तान विभाजन को रोकने के अंतरराष्ट्रीय षडयंत्र के जाने अनजाने हिस्सेदार बन रहे हैं। जम्मू कश्मीर का वर्तमान नेतृत्व और फारूख अब्दुल्ला तथा उनकी पार्टी ढुलमुल और राष्ट्रविरोधी लाइन लेती रही है। यहां तक कि जब वे भाजपा के अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री थे तब वे भाजपा के प्रचार में छिंदवाड़ा आये थे। तब उन्होंने सार्वजनिक बयान दिया था कि पीओके की सीमा को एलएसी याने लाइन आफ एक्चुअज कंट्रोल की सीमा मानना चाहिए जो कि एक राष्ट्रद्रोही बयान था। यह भी आश्चर्यजनक तथ्य है कि संघ नियंत्रित भाजपा सरकार में वे यथावत मंत्री बने रहे।

पीओके को वापिस लेने का भारत के लिये यह सबसे उपयुक्त समय है। इस समय पाकिस्तान बिखराव के चरम पर है। वह कर्ज से गले तक डूब चुका है, अर्थव्यवस्था कमजोर है और निर्वाचित जनप्रतिनिधि जेलों में बंद हैं तथा सैन्य सत्ता अपने मोहरों के माध्यम से बूंदक के दम पर सत्ता को टिकाये हुए है। अगर आज भारत पीओके को वापिस लेने के लिये सैन्य हस्तक्षेप करेगा तो उसे वैश्विक और विदेश नीति के स्तर पर पाकिस्तान के जनमत और हालात में तथा संयुक्त राष्ट्र संघ में भी कोई विशेष चुनौती का सामना नहीं करना पड़ेगा। बल्कि पाकिस्तान के जो लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित नेता हैं, जिन्हें किसी न किसी आधार पर जेल में बंद कर सेना अपने मोहरों से सरकार चला रही है वह भी सेना की कमजोरी से आजाद हो सकेंगे और पाकिस्तान में लोकतंत्र की बहाली हो सकेगी। यदि भारत ने कुशलतापूर्वक अपनी भूमिका अदा की तो पख्तूनिस्तान और बलूचिस्तान भी आजाद हो सकते हैं।

देश को पश्चिमी सीमाओं के तनाव से मुक्ति मिल सकती है। कश्मीर समस्या हल हो सकती है। चीन द्वारा साहूकारी रूपी विदेश नीति के माध्यम से जो पाकिस्तान का इस्तेमाल वन रोड वन बेल्ट जैसी योजनाओं के माध्यम से तथा व्यापार की महत्वपूर्ण योजनाओं में किया जा रहा है उसे भी रोका जा सकता है। चाबहार बंदरगाह का ठेका ईरान ने भारत को दिया। ईरान और भारत के रिश्ते भी इस निर्णायक कदम में सहयोगी होंगे। ईरान एक शिया बहुल देश है और उसकी यह संरचना भारत के समर्थन का आधार भी हो सकती है।

अगर हम भारत और भारतीय के रूप में विचारकर इस अवसर का प्रयोग करेंगे तो फिर एक बार भारत की व्यापक एकता को हासिल करने का यह उपयुक्त अवसर होगा। यदि हम राष्ट्रीय सवालों को दलीय चश्मे से देखेंगे तो फिर हम अवसर चूक जायेंगे।

अमेरिका के इतिहास में पहली बार पूर्व राष्ट्रपति अपराधिक मामलों में दोषी करार

किशन भावनानी

वैश्विक स्तर पर पूरी दुनियां में जहां लोकतंत्र के सबसे बड़े देश भारत में 19 मई से 01 जून 2024 तक दुनियां का सबसे बड़ा चुनावी महापर्व चला, वहीं लोकतंत्र के सबसे पुराने देश अमेरिका के इतिहास में पहली बार दिनांक 31 मई 2024 को किसी पूर्व राष्ट्रपति को 34 मामलों में दोषी पाया गया, तो वहीं दूसरी तरफ हांगकांग में भी वहां की संसद द्वारा बनाए गए नए कानून के तहत लोकतंत्र के समर्थक 14 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, परंतु भारत में दिनांक 4 जून 2024 को लोकतंत्र के हीरो याने सांसद कौन बनते हैं, किसकी सरकार बनती है यह निश्चित हो जाएगा। जबकि अमेरिका में आगामी 5 नवंबर 2024 को राष्ट्रपति के चुनाव होने हैं,जिसमें अनेकों उम्मीदवारों के नाम थे लेकिन अब मुख्य मुकाबले की दौड़ में दो व्यक्तियों के होने का अनुमान है परंतु 31 मई 2024 को आई खबर ने पूरे विश्व की नज़रें अमेरिका की ओर घुमा दी हैं क्योंकि राष्ट्रपति पद के प्रबल उम्मीदवार पर न्यूयार्क कोर्ट ने 34 आरोपों में दोषी करार दिया गया है, जिन पर 11 जुलाई 2024 को सजा का ऐलान किया जाएगा, जो 4 वर्ष तक कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। परंतु सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि अमेरिकी संविधान में कोई भी किसी भी आरोप का दोषी चुनाव लड़ सकता है जो जेल में ही क्यों ना हो, जीत सकता है, सरकार भी बन सकता है और जेल से सरकार भी चला सकता है, जो उसके पावर

से बाहर रहकर उपराष्ट्रपति वह अन्य पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर चला सकते हैं। परंतु इससे अमेरिका में संवैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न होने का अंदेशा जताया जा रहा है, जो चिंतनीय है। हालांकि पूर्व राष्ट्रपति ने इसका विरोध उपरी कोर्ट में अपील करने की बात कही है, वही फैसला देने वाले जजों पर भी उंगली उठा दी है। बता दें कि राष्ट्रपति का नॉमिनेशन फार्म 5 जुलाई 2024 को भरा जा सकता है, जबकि सजा का ऐलान 11 जुलाई को होगा। चूंकि अमेरिका के इतिहास में पहली बार किसी पूर्व राष्ट्रपति को अपराधों में दोषी साबित किया गया है, इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप 34 मामलों में दोषी करार, सजा का ऐलान 11 जुलाई 2024 को होगा।

अगर हम अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति को दिनांक 31 मई 2024 को न्यूयार्क की कोर्ट द्वारा दोषी करार देने की करें तो, अमेरिका के लिए 31 मई 2024 की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है लेकिन ये पन्ना अमेरिका के काले सच को बयां कर रहा है। क्योंकि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति को पोर्न स्टार केस में दोषी करार दिया गया है। 11 जुलाई को न्यूयार्क कोर्ट उन्हें इस मामले में अब सजा सुनाएगा। वे किसी मामले में दोषी पाए जाने वाले अमेरिका के पहले पूर्व राष्ट्रपती भी बन गए हैं। हालांकि अमेरिका के कई राष्ट्रपति कई आरोपों से घिरे रहे लेकिन अभी तक अमेरिका का इन राष्ट्रपतियों पर दोष सिद्ध नहीं हो पाया। लेकिन पोर्न स्टार वाले मामले में अब ऐसा हो चुका है। न्यूयार्क कोर्ट की ज्यूरी ने पोर्न स्टार को चुप कराने के लिए किए गए भुगतान को छिपाने के लिए व्यावसायिक रिकॉर्ड में हेराफेरी करने के सभी 34 मामलों में दोषी पाया है उनको फिलहाल बिना जमानत के रिहा किया गया है। ये केस अब अमेरिका का ऐसा पहला मामला बन गया है जिसमें अपराधी कोई और नहीं बल्कि अमेरिका समेत पूरी दुनियां का सबसे ताकतवर पद पर रहा शख्स यानी अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति है। (1) उन पर बिजनेस रिकॉर्ड में हेरफेर का आरोप लगा है। गलत बिजनेस रिकॉर्ड दिखाने के मामले में 34 चार्ज लगाए गए हैं। ये सभी चार्ज 2016 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले पोर्न स्टार को चुप रहने के लिए 1 लाख 30 हजार डॉलर करीब 1 करोड़ 70 लाख की राशि दी गई है। (2) उन पर लगाए गए 11 आरोप चेक साइन करने से जुड़े हैं। वहीं 11 मामले ट्रंप के पूर्व निजी वकील की लीगल कंपनी में जमा किए गए गलत इनवॉइस के हैं। (3)- इसके अलावा 12 मामले उनके रिकार्ड्स में गलत जानकारी को लेकर लगाए हैं। बता दें कि कोर्ट उनको 11 जुलाई को फैसला सुनाएगा। जो कि अमेरिका के चुनाव के

लिहाज से अहम है क्योंकि 11 जुलाई के कुछ दिन बाद ही मिल्वौकी में रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन होना है। जिसमें उनके उनके समर्थन में ग्रांड ओल्ड पार्टी के नेता उन्हें अपना औपचारिक तौर पर राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित करते। उनको गुप्त धन मामले से जुड़े सभी 34 मामलों में दोषी पाया गया है। इसी के साथ वे अमेरिका के इतिहास के पहले पूर्व राष्ट्रपति बने हैं, जिन्हें घोर अपराध का दोषी करार दिया गया है। उन पर 2016 में व्हाइट हाउस में आने से पहले पूर्व पोर्न स्टार के साथ अपने यौन संबंधों को छिपाने के लिए व्यापारिक रिकॉर्ड में हेराफेरी करने का आरोप है। इस मामले में 34 आरोप, 11 चालान, 12 वाउचर और 11 चेक पेश किए गए। मैनहट्टन के 12 जूरी सदस्यों ने कहा कि वे ट्रंप ने 2016 के राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित करने के लिए एडल्ट स्टारको 130 हज़ार अमेरिकी डॉलर का गुप्त भुगतान किया। इसे छुपाने के लिए उन्होंने व्यावसायिक रिकॉर्ड में हेराफेरी की। जूरी ने कहा कि उनको राष्ट्रपति चुने जाने से नहीं रोका जा सकता और अब यह 5 नवंबर को मतदाताओं पर ही निर्भर करेगा। जूरी ने 22 गवाहों के बयानों के आधार पर यह फैसला सुनाया, जिनमें एडल्ट स्टार भी शामिल थीं।

अगर हम न्यूयार्क कोर्ट के फैसले पर पूर्व राष्ट्रपति की प्रतिक्रिया की करें तो, सजा पर सुनवाई के लिए 11 जुलाई को सुबह 10 बजे का समय निर्धारित किया है। खास बात यह है कि 11 जुलाई से ठीक चार दिन पहले मिल्वौकी मेंरिपब्लिकन पार्टी की बैठक होगी, जहां ट्रंप को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया जाना है। जिस समय यह फैसला सुनाया गया, उस समय ट्रंप शांत रहे लेकिन, कोर्ट से बाहर निकलकर उन्होंने इस फैसले को शर्मनाक बताया। जूरीके फैसले पर कहा कि यह अपमानजनक था। उन्होंने कहा कि यह एक विवादित और भ्रष्ट न्यायाधीश द्वारा किया गया मुकदमा था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने कहा 5 नवंबर को असली फैसला जनता की अदालत में होगा। जनता जानती है कि असली सच क्या है। हम जानते हैं कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया। मैं अपने देश के लिए लड़ रहा हूं, मैं अपने देश के संविधान के लिए लड़ रहा हूं। इस समय हमारे देश में धांधली हो रही है।उन्होने आरोप लगाया कि राष्ट्रपति बाइडन ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी को चोट पहुंचाने के लिए जान-बूझकर ऐसा किया हैउन्होने ज्यूकरी में शामिल जज पर एक और गंभीर आरोप लगाया, उन्होंने कहा था कि वे नहीं चाहते कि उनके खिलाफ लगाए गए फर्जी आरोपों पर एक मत से फैसला हो। पूर्व राष्ट्रिपति ने जज के व्यवहार को बेकार, असंवैधानिक और अमेरिका विरोधी करार दिया। वहीं, जज ने असल में ज्यूरी के सभी सदस्यों से कहा था कि सभी 34 मामलों में फैसला

एकमत से लिया जाना चाहिए। न्यूयार्क इलेक्शन लॉ का मसला उठने के बाद जज ने कहा था कि ज्यूरी के अन्या सदस्यों को ट्रंप द्वारा अपनाए गए गैरकानूनी तरीकों पर फैसला लेने में एक राय होने की जरूरत नहीं है।

अगर हम इस मामले पर वर्तमान राष्ट्रपति की प्रतिक्रिया की करें तो, उनकी तरफ से आई प्रतिक्रिया हालांकि ट्रंप अभी भी चुनाव लड़ने के योग्य हैं और वो चुनाव लड़ सकते हैं। बाइडेन के चुनाव अभियान ने एक बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि कोई भी कानून से उपर नहीं होता। उन्होने हमारे लोकतंत्र के लिए जोखतरा पैदा किया है, वो पहले कभी इतना बड़ा नहीं था।उधर बाइडन हैरिस अभियान ने जूरी के फैसले का स्वागत किया है। बिडेन-हैरिस 2024 के संचार निदेशक ने कहा कि अमेरिका में कानून से उपर नहीं है। आगे कहा कि ट्रम्प ने हमेशा इस बात पर भरोसा किया कि कानून तोड़ने पर उन्हें परिणाम भुगतना नहीं पड़ेगा लेकिन, इसके ठीक उलट हुआ है।

अगर हम अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने पर सस्पेंस की करें तो, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति खुद को फिर से व्हाइट हाउस में देखना चाहते हैं इसके लिए वो 5 नवंबर को होने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की जी तोड़ तैयारी कर रहे हैं। प्राइमरी इलेक्शन में उन्होंने बंपर जीत हासिल की है। हालांकि अब जब उन्हें दोषी करार दिया गया और सजा भी सुनाई जानी है तो भी उनके चुनाव लड़ने पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति उम्मीदवार का नियम भारत की तरह सख्त नहीं है। यहां पर नियमों के मुताबिक उम्मीदवार (1) संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्मा व्यक्तिहै। (2) अमेरिका की ही नागरिकता हो। (3) कम से कम 35 वर्ष का हो। (4) 14 सालों से संयुक्तराज्य अमेरिका के निवासी हो, यानी वे अभी भी चुनाव लड़ सकते हैं और वो सजा काटने के दौरान भी चुनाव लड़सकते हैं और अगर जीत जाते हैं तो राष्ट्रपति भी बन सकते हैं। हालांकि, उनके वकीलों नेट्रायल को गलत बताया है और कहा है कि वो इसके खिलाफ उच्च अदालत में अपील करेंगे। मीडिया मुताबिक उनको जेल हो सकती है। वहीं, कुछ लीगल एक्सपर्ट्स का मानना है कि उन्हें जुर्माना भरवाकर छोड़ा जा सकता है। न्यूयार्क शहर का प्रोबेशन डिपार्टमेंट ट्रम्प का इंटरव्यू करेगा। इंटरव्यू के दौरान दोषी पाया गया शख्स अपनी अच्छी इमेज बनाने की कोशिश करता है। ये दलील देता है कि उसे क्यों कम से कम सजा मिलनी चाहिए। वे अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य के निवासी हैं। वहां ये नियम है कि अगर कोई शख्स किसी आपराधिक मामले में दोषी पाया जाता है तो उससे वोट करने का अधिकार छीन लिया जाता है। ऐसे में ट्रम्प के साथ भी ऐसा हो सकता है। हालांकि, अगर ऐसे प्रावधान भी हैं जिससे वो अपने वोटिंग राइट्स फिर से हासिल कर सकते हैं। उनकी सजा पर सुनवाई के बाद ही ये कहा जा सकता है कि उनके वोटिंग राइट्स छीने जाएंगे या नहीं।

ठेके की नौकरियों में गुम होता भविष्य

पद्माकर त्रिपाठी

वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम के एक नये सर्वे से पता चला है कि देश में सरकारी और गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों में नौकरियां नियत मानदेय और ठेके पर दी जा रही है। यानी स्थाई नौकरी के अवसर तेजी से खत्म हो रहे हैं। कंपनियों और सरकारी विभागों की इस नीति के चलते कर्मचारियों के जीवन स्तर, कार्य क्षमता और मनोबल पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। यह बदहाली सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, दूरसंचार, ऑटोमोबाइल, निर्माण, आईटी, बीपीओ, पर्यटन वगैरह सभी क्षेत्र में बढ़ रही है। अपवादस्वरूप सेना, अर्थ सैनिक बल, पुलिस, वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे चुनिंदा क्षेत्र ही फिलहाल इस व्यवस्था से बचे हैं।

रिपोर्ट के अनुसार रोजगार के मामले में सरकारी-गैरसरकारी दोनों क्षेत्रों में श्रम कानूनों का खुला उल्लंघन हो रहा है। कानूनों के पालन की बात करें तो कामगारों से नियम सम्मत कार्य अवधि तक काम लेने के अलावा बाकी कुछ कानूनी नहीं होता है। यह स्थिति से केन्द्र और राज्य सरकारों की ओर से बेरोजगारी खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर बढ़ाये जाने संबंधी दावों का सच दिखा रही है।

कई क्षेत्रों में शारीरिक व मानसिक रूप से थके हुए सेवानिवृत्त लोगों और निर्धारित मानकों से बहुत नीचे की योग्यता रखने वाले लोगों को भी मानदेय पद्धति के आधार पर काम पर रखकर काम चलाऊ ढांचा विकसित किया जा रहा है। गौरतलब है कि प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा में उसी कामचलाऊ ढांचे की गुणवत्ता और कार्य क्षमता पर कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षामित्र पर काम करने वालों को शिक्षाशत्रु की संज्ञा दी थी।

असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को पुलिस और प्रशासनिक अधिकार प्राप्त दूसरे लोगों के शोषण से बचाने के लिए बनाये गये नये कानून पथ विक्रेता जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन अधिनियम-2012 में भी उन लोगों के हितों की सुरक्षा होती नहीं दिख रही है। इस नजरिये से शिक्षित, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक अथवा तकनीकी शिक्षा प्राप्त बेरोजगारों के रूप को परिभाषित करने के लिए कोई कारगर

श्रेणीबद्ध तंत्र भी विकसित नहीं किया जा सका है।

यही कारण है कि शैक्षिक लोन लेकर पढ़ाई करने वाले लोगों में से ज्यादातर की हैसियत बैंक का लोन चुका पाने की भी नहीं बन पा रही है। ऐसे युवा अपने नियोक्ताओं, कम्पनियों के साथ ही वित्तीय संस्थानों के हाथों उनके मन-मुताबिक काम करने को मजबूर हैं। शायद इसी कारण मजबूर लोग सरकार की ओर से लोन माफी के अवसरों की बाट जोहते हैं।

इस व्यवसाय में तमाम लोगों को केन्द्र और राज्य सरकारों की ओर से चलायी जा रही समाज कल्याण योजनाओं का लाभ भी नहीं के बराबर मिल पाता है। इससे पहले उन्हीं लोगों को ध्यान में रख कर चलायी गयी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में पांच सदस्यों वालें पंजीकृत परिवारों को बीमार पड़ने पर इलाज के लिए 30,000 रुपये तक के आर्थिक सहयोग की बात कही गयी है। लेकिन रेहड़ी, ठेला, खोमचा, फेरी, रिक्शा चालन जैसे रोजगार करने वालों के साथ ही मानदेय पर काम करने वाले लोग भी उस योजना के लाभ से वंचित हैं।

मौसम बेराजगारी या दूसरी मजबूरियों के कारण रोजगार बदलने की स्थिति में प्रभावित लोगों को उसका लाभ किसी रूप में नहीं होने वाला है। ऐसे में, ठेके या मानदेय पर काम कर रहे लोगों की स्थिति कहीं ज्यादा कठिन हो गयी है। विशेष अवसरों पर बड़े स्तर पर आर्थिक सहयोग, चिकित्सा सहायता, सामाजिक व व्यावसायिक सुरक्षा, पेंशन, जीपीएफ, ग्रेच्युटी, जीवन बीमा, भविष्य निधि, शिक्षा निधि जैसे कोई सुविधा इन्हें मुहैया नहीं है। देश भर में श्रमिक सुरक्षा व कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम वेतन, फैक्टरी एक्ट, बाल श्रम निरोधक जैसे ज्यादातर श्रम कानूनों को ठेंगा दिखाया जा रहा है।

उन नीतियों के चलते स्थाई नौकरी करने वाले लोगों की तरह अस्थाई कार्मिकों की

व्यवस्थित कार्य स्थिति नहीं बन पा रही है। आज नियोक्ता ज्यादा वेतन पर काम करने वाले प्रशिक्षित और अनुभवी लोगों की बजाय कम मानदेय अथवा ठेके पर काम करने वाले अप्रशिक्षित और कम अनुभवी कामगारों को प्राथमिकता देते हैं।

अकेले उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा में पीएचडी, नेट, जेआरएफ, स्लेट और समकक्ष दूसरी योग्यता रखने वाले एक लाख से ज्यादा लोग विश्वविद्यालय में मानदेय पर शिक्षण कार्य कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सरकार की ओर से तय पैमाने से कम मानदेय दिया जाता है। ग्रामीण और पिछड़े इलाकों के शिक्षण संस्थानों में काम करने वाले ऐसे शिक्षकों की हालत तो और भी दयनीय है। कमोबेश यही हाल प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का भी है। चुनाव आयोग के लिये भी देश भर में कई सालों से नियमित रूप से सेवायें देने वाले लाखों कार्मिक उसी मानदेय पद्धति के हैं।

देश में कर्मचारियों, बैंकिंग, बीमा व दूसरे क्षेत्रों के लिए भी नये वेतनमान देने की तैयारियां हो रही हैं। दूसरी ओर नियमित नौकरी के एवज में ज्यादा वेतन पाने वाले लोगों की तुलना में अपर्याप्त मानदेय और दैनिक मजदूरी पर काम कर रहे लोग लगातार बढ़ती महंगाई के चलते बहुत बदहाली में जी रहे हैं।

इस विसंगति का सीधा प्रभाव कर्मचारियों की कार्यशैली, कार्य क्षमता और गुणवत्ता पर पड़ रहा है, जिसके नाते उसी तेजी से राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार, लापरवाही, गैर जिम्मेदारी, आधा अधूरा कार्य करने की संस्कृति विकसित हो रही है। दफ्तरों और फैक्ट्रियों के असुरक्षित वातावरण में काम करने के कारण वे असमय गंभीर रोगों के शिकार हो जाते हैं, इस तंगहाली से कार्मिकों का स्वास्थ्य, कार्यक्षमता, कार्यकुशलता और मनोबल गिर रहा है। अफसोस कि इतनी बड़ी विसंगति खत्म करने की ओर नीति कारों का ध्यान नहीं जा रहा है।

सरकारी विभागों से लेकर छोटे बड़े उद्योगों में काम करने वाले इन कर्मचारियां के दुर्घटनाग्रस्त होने, असामयिक मौत अथवा नौकरी छिन जाने पर उनके आश्रित और परिजन बेसहारा हो जाते हैं, जबकि उन हालात में भी अक्सर नियोक्त द्वारा आश्रितों को राहत देने की ठोस पहल नहीं की जाती। विडम्बना यह कि नयी नीतियों के तहत न्यूनतम पेंशन योजना सफल बनाने के तो पुरजोर प्रयास हो रहे हैं लेकिन न्यूनतम वेतन अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक और महंगाई के अनुरूप श्रमिकों को पर्याप्त वेतन मिलने का काम व्यवहार में सफल होता नहीं दिख रहा है।

Water Pollution an Invitation to health diseases

Vaibhav

It is a well-known fact that pure and clean water is absolutely essential for healthy and long living. Adequate supply of fresh and clean drinking water is a basic need for all human beings on the earth, yet the fact is that millions of people worldwide are deprived of this.

Freshwater resources all over the world are threatened not only by over exploitation and poor management but also by ecological degradation. The main source of freshwater pollution can be attributed to discharge of untreated waste, dumping of industrial effluent, and run-off from agricultural fields. Industrial growth, urbanization and the increasing use of synthetic organic substances have serious and adverse impacts on freshwater bodies. It is a generally accepted fact that the developed countries suffer from problems of chemical discharge into the water sources mainly groundwater, while developing countries face problems of agricultural run-off in water sources. Polluted water like chemicals in drinking water causes problem to health and leads to water-borne diseases which can be prevented by taking measures can be taken even at the household level.

Groundwater and its contamination

Many areas of groundwater and surface water are now contaminated with heavy metals, POPs (persistent organic pollutants), and nutrients that have an adverse affect on health. Water-borne diseases and water-caused health problems are mostly due to inadequate and incompetent management of water resources. Safe

water for all can only be assured when access, sustainability, and equity can be guaranteed. Access can be defined as the number of people who are guaranteed safe drinking water and sufficient quantities of it. There has to be an effort to sustain it, and there has to be a fair and equal distribution of water to all segments of the society. Urban areas generally have a higher coverage of safe water than the rural areas. Even within an area there is variation: areas that can pay for the services have access to safe water whereas areas that cannot pay for the services have to make do with water from hand pumps and other sources.

In the urban areas water gets contaminated in many different ways, some of the most common reasons being leaky water pipe joints in areas where the water pipe and sewage line pass close together. Sometimes the water gets polluted at source due to various reasons and mainly due to inflow of sewage into the source.

Ground water can be contaminated through various sources and some of these are mentioned below.

Pesticides. Run-off from farms, backyards, and golf courses contain pesticides such as DDT that in turn contaminate the water. Leechate from landfill sites is another major contaminating source. Its effects on the ecosystems and health are endocrine and reproductive damage in wildlife. Groundwater is susceptible to contamination, as pesticides are mobile in the soil. It is a matter of concern as these chemicals are persistent in the soil and water.

Sewage. Untreated or inadequately treated municipal sewage is a major source of groundwater and surface water pollution in the developing countries. The organic material that is discharged with municipal waste into the watercourses uses substantial oxygen for biological degradation thereby upsetting the ecological balance of rivers and lakes. Sewage also carries microbial pathogens that are the cause of the spread of disease.

Nutrients. Domestic waste water, agricultural run-off, and industrial effluents contain phosphorus and nitrogen, fertilizer run-off, manure from livestock operations, which increase the level of nutrients in water bodies and can cause eutrophication in the lakes and rivers and continue on to the coastal areas. The nitrates come mainly from the fertilizer that is added to the fields. Excessive use of fertilizers cause nitrate contamination of groundwater, with the result that nitrate levels in drinking water is far above the safety levels recommended. Good agricultural practices can help in reducing the amount of nitrates in the soil and thereby lower its content in the water.

Synthetic organics. Many of the 100 000 synthetic compounds in use today are found in the aquatic environment and accumulate in the food chain. POPs or Persistent organic pollutants, represent the most harmful element for the ecosystem and for human health, for example, industrial chemicals and agricultural pesticides. These chemicals can accumulate in fish and cause serious damage to human health. Where pesticides are used on a large-scale, groundwater gets contaminated and this leads to the chemical contamination of drinking water.

Acidification. Acidification of surface water, mainly lakes and reservoirs, is one of the major environmental impacts of transport over long distance of air pollutants

such as sulphur dioxide from power plants, other heavy industry such as steel plants, and motor vehicles. This problem is more severe in the US and in parts of Europe.

Chemicals in drinking water

Chemicals in water can be both naturally occurring or introduced by human interference and can have serious health effects.

Fluoride. Fluoride in the water is essential for protection against dental caries and weakening of the bones, but higher levels can have an adverse effect on health. In India, high fluoride content is found naturally in the waters in Rajasthan.

Arsenic. Arsenic occurs naturally or is possibly aggrevated by over powering aquifers and by phosphorus from fertilizers. High concentrations of arsenic in water can have an adverse effect on health.A few years back, high concentrations of this element was found in drinking water in six districts in West Bengal. A majority of people in the area was found suffering from arsenic skin lesions. It was felt that arsenic contamination in the groundwater was due to natural causes. The government is trying to provide an alternative drinking water source and a method through which the arsenic content from water can be removed.

Lead. Pipes, fittings, solder, and the service connections of some household plumbing systems contain lead that contaminates the drinking water source.

Recreational use of water. Untreated sewage, industrial effluents, and agricultural waste are often discharged into the water bodies such as the lakes, coastal areas and rivers endangering their use for recreational purposes such as swimming and canoeing.

Petrochemicals. Petrochemicals contaminate the groundwater from underground petroleum storage tanks.

Other heavy metals. These contaminants come from mining waste and tailings, landfills, or hazardous waste dumps.

Chlorinated solvents. Metal and plastic effluents, fabric cleaning, electronic and aircraft manufacturing are often discharged and contaminate groundwater.

Disease

Water-borne diseases are infectious diseases spread primarily through contaminated water. Though these diseases are spread either directly or through flies or filth, water is the chief medium for spread of these diseases and hence they are termed as water-borne diseases.

Most intestinal (enteric) diseases are infectious and are transmitted through faecal waste. Pathogens which include virus, bacteria, protozoa, and parasitic worms are disease-producing agents found in the faeces of infected persons. These diseases are more prevalent in areas with poor sanitary conditions. These pathogens travel through water sources and interfuses directly through persons handling food and water. Since these diseases are highly infectious, extreme care and hygiene should be maintained by people looking after an infected patient. Hepatitis, cholera, dysentery, and typhoid are the more common water-borne diseases that affect large populations in the tropical regions.

A large number of chemicals that either exist naturally in the land or are added due to human activity dissolve in the water, thereby contaminating it and leading to various diseases.

Pesticides. The organophosphates and the carbonates present in pesticides affect and damage the nervous system and can cause cancer. Some of the pesticides contain carcinogens that exceed recommended levels. They contain chlorides that cause reproductive and endocrinal damage.

Lead. Lead is hazardous to

health as it accumulates in the body and affects the central nervous system. Children and pregnant women are most at risk.

Fluoride. Excess fluorides can cause yellowing of the teeth and damage to the spinal cord and other crippling diseases.

Nitrates. Drinking water that gets contaminated with nitrates can prove fatal especially to infants that drink formula milk as it restricts the amount of oxygen that reaches the brain causing the 'blue baby' syndrome. It is also linked to digestive tract cancers. It causes algae to bloom resulting in eutrophication in surface water.

Petrochemicals. Benzene and other petrochemicals can cause cancer even at low exposure levels.

Chlorinated solvents. These are linked to reproduction disorders and to some cancers.

Arsenic. Arsenic poisoning through water can cause liver and nervous system damage, vascular diseases and also skin cancer.

Other heavy metals. Heavy metals cause damage to the nervous system and the kidney, and other metabolic disruptions.

Salts. It makes the fresh water unusable for drinking and irrigation purposes.

Exposure to polluted water can cause diarrhoea, skin irritation, respiratory problems, and other diseases, depending on the pollutant that is in the water body. Stagnant water and other untreated water provide a habitat for the mosquito and a host of other parasites and insects that cause a large number of diseases especially in the tropical regions. Among these, malaria is undoubtedly the most widely distributed and causes most damage to human health.

Preventive measures

Water-borne epidemics and

health hazards in the aquatic environment are mainly due to improper management of water resources. Proper management of water resources has become the need of the hour as this would ultimately lead to a cleaner and healthier environment.

In order to prevent the spread of water-borne infectious diseases, people should take adequate precautions. The city water supply should be properly checked and necessary steps taken to disinfect it. Water pipes should be regularly checked for leaks and cracks. At home, the water should be boiled, filtered, or other methods and necessary steps taken to ensure that it is free from infection.

Minamata: environmental contamination with methyl mercury

In Minamata, Japan, inorganic mercury was used in the industrial production of acetaldehyde. It was discharged into the nearby bay as waste water and was ingested by organisms in the bottom sediments. Fish and other creatures in the sea were soon contaminated and eventually residents of this area who consumed the fish suffered from MeHg (methyl mercury) intoxication, later known as the Minamata disease. The disease was first detected in 1956 but the mercury emissions continued until 1968. But even after the emission of mercury stopped, the bottom sediment of the polluted water contained high levels of this mercury.

Various measures were taken to deal with this disease. Environmental pollution control, which included cessation of the mercury process; industrial effluent control, environmental restoration of the bay; and restrictions on the intake of fish from the bay. This apart research and investigative activities were promoted assiduously, and compensation and help was offered by the Japanese Government to all those affected by the disease.

The Minamata disease proved a turning point, towards progress in environment protection measures. This experience clearly showed that health and environment considerations must be integrated into the process of economic and industrial development from an early stage.

जगत पाठक पत्रकारिता संस्थान, भोपाल

जगत पाठक पत्रकारिता संस्थान वर्ष 1998 से सतत् रूप से संचालित हो रहा है। इस संस्थान से अध्ययन कर छात्र-छात्राएं प्रिंट व इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में अच्छे पदों पर पदस्थ हैं। साथ ही साथ शासकीय पद पर आसीन होकर इस संस्थान को गौरवान्वित कर रहे हैं।

: विषय :

मास्टर ऑफ आर्ट जर्नलिज्म (2 वर्ष)

प्रवेश प्रारंभ

संपर्क सूत्र

विजया पाठक (संचालक) - 9826064596

अर्चना शर्मा - 9754199671

कार्यालय - कार्पोरेट कार्यालय - एफ 116/17, शिवाजी नगर, भोपाल, म.प्र.

संस्थान - 28, सुरभि विहार कालोनी, कालीबाड़ी, बी.डी.ए. रोड, भेल, भोपाल, म.प्र.